शर्मा शर्डअवेब
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in

हिंदी दैनिक

गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 243 | गुवाहाटी | बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी- जल्द खत्म हो सकती है पूरी सभ्यता — पेज 2

पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शांति लौटने के बाद विकास के पथ पर अग्रसर... — पेज 3

उप्र कैबिट : योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में मेट्रो विश्वविद्यालय की स्थापना को दी मंजूरी — पेज 5

फीफा वर्ल्ड कप 2026 : सोफी स्टेडियम के कर्मचारियों की चेतावनी... — पेज 7

door graph
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

अपने हित से पहले, समाज और देश के हित को देखना एक विवेक युक्त सच्चे नागरिक का धर्म होता है।

– ईश्वर चंद्र विद्यासागर

न्यूज गैलरी

असम में भूकंप के झटके, लोग घरों से निकले बाहर

गुवाहाटी (हि.स.)। असम में मंगलवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका दोपहर 02 बजकर 18 मिनट 31 सेकेंड पर महसूस किया गया। भारतीय सिस्मोलॉजी केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई। इसका केंद्र असम के हैलाकांदी जिले में जमीन के अंदर करीब 5 किलोमीटर *–शेष पृष्ठ दो पर*

कर्नाटक में कई अधिकारियों के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा

बेंगलुरु (हि.स.)। कर्नाटक राज्य के विभिन्न जिलों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कर्नाटक लोकायुक्त अधिकारियों ने मंगलवार सुबह कई सरकारी अधिकारियों के यहां एक साथ छापा मारा। लोकायुक्त टीम ने आज सुबह चित्रदुर्ग जिले के निर्माण केंद्र में कार्यरत असिस्टेंट अकाउंटेंट सुशीलम्मा के मेदेहल्ली रोड स्थित निवास और हिरियूर के यारदकट्टे स्थित फार्महाउस में ठिकानों पर *–शेष पृष्ठ दो पर*

असम विस चुनाव : प्रचार थमा, कल मतदान, मैदान में कुल 722 उम्मीदवार

गुवाहाटी (हि.स.)। आसन्न 16वीं असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को होने जा रहे मतदान के मद्देनजर मंगलवार की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार अभियान पूरी तरह से समाप्त हो गया। उम्मीदवार आगामी बुधवार को अनौपचारिक रूप से घर-घर प्रचार अभियान चला सकेंगे। इस बीच मतदान कर्मी बुधवार को अपने पोलिंग स्टेशनों की ओर रवाना होंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दूर-दराज के पोलिंग स्टेशनों के लिए खासकर राज्य के पहाड़ी जिले डिमा हसाओ और कार्बी आंग्लांग जिलों के कुछ पोलिंग स्टेशनों के लिए मतदान कर्मी मंगलवार को ही रवाना हो गये। कारण वे आज रवाना होकर बुधवार तक अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। राज्य की सत्ताधारी पार्टी भाजपा की ओर से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज तीन चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जबकि, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा मध्य असम और ऊपरी असम में चुनाव प्रचार किया। वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोरव गोगोई समेत अन्य नेताओं ने भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी। इस बार के चुनाव में अंतिम समय में कांग्रेस पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगाए गये आरोपों के मद्देनजर प्रचार के दौरान बयानों में मर्यादाएं भी तार-तार हो गयीं। दोनों ओर से बीते दो दिनों से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे चुनावी माहौल बेहद गर्म हो गया है। चुनाव प्रचार अभियान के अंतिम दिन निर्धारित आदर्श आचार संहिता के नियमों के अनुसार शाम 5 बजे प्रचार अभियान का समापन हो गया। आज से कोई भी औपचारिक रूप से प्रचार अभियान नहीं चला सकता। इस बीच चुनाव प्रचार अभियान के अंतिम दिन सुबह से ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का माहौल उत्साहपूर्ण देखा गया। विधानसभा चुनाव के लिए शासक और विपक्ष दोनों ही पक्ष मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जोरदार प्रचार अभियान चलाते नजर आए। दिन-रात यह प्रचार अभियान जारी रहा। इस संदर्भ में, सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए व्यापक प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जोरदार प्रचार कर भाजपा की रणनीतियों को लोगों के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को बरपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ समेत तीन सार्वजनिक सभाओं में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले भी एक अप्रैल को असम आकर चुनाव प्रचार में भाग ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने धेमाजी के गोगामुख और बिश्वनाथ के बिहाली में आयोजित दो चुनावी जनसभाओं में भाग लेकर दल के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। इसी तरह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने व्यापक प्रचार अभियान चलाया। इसी तरह अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी भरपूर प्रयास किया। चुनाव प्रचार अभियान के बीच रविवार से असम की राजनीति में दो नाम सबसे अधिक चर्चित हो गए हैं। ये दोनों हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा। पवन खेड़ा ने रिनिकी भुइयां शर्मा द्वारा कई देशों के पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। उल्लेखनीय है कि 16वीं असम विधानसभा के लिए 722 उम्मीदवार चुनाव में भाग ले रहे हैं। इनमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 663 है और महिला उम्मीदवारों की संख्या 59 है। दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी ने 18 सीटों, सीपीआई (एम) ने दो सीटों, असम गण परिषद ने 26 सीटों, एआईयूडीएफ ने 30 सीटों, बीपीएफ ने 11 सीटों, यूपीपीएल ने 18 सीटों, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने दो सीटों, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटों, अपना जनता पार्टी ने दो सीटों, असम राष्ट्रीय परिषद ने 10 सीटों, भारतीय जनता परिषद ने चार सीटों, सीपीआई ने तीन सीटों, पीआई (एमएल) ने तीन सीटों, जन सुरक्षा पार्टी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसी तरह से गोंडवाना लोकतांत्रिक पार्टी ने तीन सीटों, झाड़खंड मुक्ति मोर्चा ने 16 सीटों, नेशनल पीपल्स *–शेष पृष्ठ दो पर*

मणिपुर में धमाका, दो बच्चों की मौत चार जिलों में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद

इंफाल। मणिपुर के बिष्णुपुर में बम हमले के बाद हुई हिंसा के चलते मणिपुर की घाटी के चार जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। इस हमले में दो बच्चों की मौत हो गई थी। इससे क्रुद्ध स्थानीय लोगों के हिंसक विरोध-प्रदर्शन में तेल टैंकर जलाने से लेकर अस्थायी पुलिस चौकी तक नष्ट की गई है। मुख्यमंत्री ने इस हमले को *बर्बर कृत्य* करार दिया और लोगों को आश्वासन दिया कि अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर सरकार ने दो बच्चों की जान लेने वाले बम हमलों की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला किया है। पुलिस के अनुसार यह घटना देर रात एक बजे हुई जब संदिग्ध उग्रवादियों ने मोइरांग ट्रोंग्लाओबी क्षेत्र में एक घर पर बम फेंका। इस हमले में 5 वर्षीय लड़के और 6 महीने की दुधमुंही बच्ची की मौत हो गई। दोनों बच्चे और उनकी मां अपने बेडरूम में सो रहे थे जब घर में बम विस्फोट किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सुबह विरोध प्रदर्शन किया और क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास दो तेल टैंकर और एक ट्रक को आग लगा दी। उन्होंने मोइरांग पुलिस स्टेशन के सामने टायर जलाए और एक अस्थायी पुलिस चौकी को नष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ट्रोंग्लाओबी के पास एक विस्फोटक उपकरण भी बरामद किया गया। मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने कहा कि यह मानवता पर सीधा हमला है और मणिपुर में अर्जित शांति को बाधित करने का प्रयास है। ऐसे उग्रवादी कृत्यों को किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। मणिपुर सरकार हर नागरिक की सुरक्षा के *–शेष पृष्ठ दो पर*

असम भाजपा ने खड़गे के खिलाफ पुलिस और राज्य चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत

गुवाहाटी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की असम इकाई ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) में शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने उन पर राज्य में एक चुनावी रैली में कथित *नफरती भाषण* देने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता प्रांजल कलिता ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस नेता बार-बार संविधान का पालन करने का दावा करते हैं। लेकिन उनके कार्य सांविधानिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों की प्रति सम्मान की मूल भावना के घोर विपरीत हैं। कलिता ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)-भाजपा पर प्रतिबंध लगाने की खड़गे की हालिया मांग न केवल राजनीतिक असहिष्णुता को दर्शाती है। बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भीतर बौद्धिक दिवालिया पन को भी उजागर करती है। उन्होंने आगे कहा कि असम प्रदेश भाजपा श्रीभूमि जिले के नीलम बाजार में छह अप्रैल को एक चुनावी रैली के दौरान की *–शेष पृष्ठ दो पर*

पवन खेड़ा पर असम सरकार की कार्रवाई, कांग्रेस का दावा- विपक्ष को डराने और आवाज दबाने की कोशिश

गुवाहाटी / नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और कांग्रेस के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। असम पुलिस की एक टीम ने आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास का दौरा किया। यह कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और उनके परिवार के खिलाफ खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े एक मामले के संबंध में की गई। कांग्रेस ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने के लिए राज्य मशीनरी का दुरुपयोग बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस की पूरी टीम पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए भेजी गई, वह दिखाता है कि असम के मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं और उन पर हार का खतरा मंडरा रहा है। यह घटना असम में गुरुवार को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार चरम पर हुई है। शर्मा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूह से झूठी जानकारी का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन आरोपों को असम चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास और एक दंडनीय अपराध बताया था। खेड़ा ने 5 अप्रैल को एक प्रेस वार्ता में शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर तीन देशों के पासपोर्ट *–शेष पृष्ठ दो पर*

विस चुनाव खत्म होते ही शुरू होगा एसआईआर का अंतिम चरण

नई दिल्ली। देश में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाने के लिए निर्वाचन आयोग एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। केरल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को आने हैं। इसके तुरंत बाद, चुनाव आयोग देश के बाकी बचे 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का तीसरा और अंतिम चरण शुरू कर सकता है। न्यूज एजेंसी ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि इस सफाई अभियान के तहत अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में काम पूरा हो चुका है। अब तक लगभग 60 करोड़ मतदाताओं का डाटा वेरिफाई किया जा चुका है। अब बारी बाकी बचे 39 करोड़ मतदाताओं की है, जो दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और *–शेष पृष्ठ दो पर*

हैट्रिक की राह में महंगाई बना सबसे बड़ा रोड़ा

गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल जोर-शोर से चुनावी रैलियां कर रहे हैं। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सत्ता के वनवान का अज्ञातवास खत्म होने की आस लगाए बैठी है। बता दें कि साल 2016 में राज्य में पहली बार भाजपा जीत हासिल कर सत्ता में आई थी। ऐसे में विपक्षी दल लगातार सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ मुद्दे उठाकर पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में असम चुनाव के यह मुद्दे सत्ता दल के लिए टेंशन बढ़ा सकते हैं। *–शेष पृष्ठ दो पर*

आरएसएस मुख्यालय के पास विस्फोटक बरामद, नागपुर में हड़कंप

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के पास विस्फोटक मिलने से सनसनी फैल गई है, जिसके बाद शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं फोरेंसिक टीम भी छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि इलाके में एक बैग रखा था, जिससे 15 जिलेटिन स्टिक, 50 डेटोनेटर और 8 कनेक्टर बरामद किए गए हैं। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक नागपुर के सीए रोड स्थित दोसर भवन चौक इलाके में भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। मेट्रो स्टेशन के पास एक घर के छोटे गार्डन में एक बैग रखा था, जिससे 15 जिलेटिन स्टिक, 50 डेटोनेटर और 8 कनेक्टर बरामद किए गए हैं। मंगलवार (7 अप्रैल) सुबह घर के मालिक की नजर इस बैग में रखी जिलेटिन स्टिक पर पड़ी, जिसके बाद उसने बिना देर के लिए फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस, बम निरोधक दस्ता *–शेष पृष्ठ दो पर*

पाकिस्तान को राजनाथ की चेतावनी

कोलकाता पर हमला हुआ तो टुकड़े-टुकड़े कर देंगे

कोलकाता (हि.स.)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ द्वारा कोलकाता पर हमले की धमकी देने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इस तरह की भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बचना चाहिए, अन्यथा उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए *–शेष पृष्ठ दो पर*

90 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटे

घुसपैठियों के बाहर होते ही पश्चिम बंगाल में मचा सियासी तूफान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बार एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। वर्षों से जिस सवाल को दबाया जाता रहा, जिस पर चर्चा होते ही सियासत गर्म हो जाती थी, अब उसी मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई हुई है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया ने राज्य की चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। करीब नब्बे लाख नामों का मतदाता सूची से हटाया जाना साफ संदेश है कि अब चुनावी व्यवस्था में ढील नहीं चलेगी। देखा जाए तो दशकों बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है जिसमें केवल वही लोग मतदान करेंगे जो वास्तव में इसके पात्र हैं। पहले स्थिति यह थी कि मतदाता सूची पर लगातार सवाल उठते थे। आरोप लगते थे कि बाहरी लोग, अवैध घुसपैठिये और अपात्र *–शेष पृष्ठ दो पर*

आधुनिक विकास को परंपराओं और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ना जरूरी : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली (हि.स.)। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने मंगलवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के 39वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वैज्ञानिक प्रगति और आधुनिक विकास को नैतिक मूल्यों और भारतीय परंपराओं के साथ संतुलित करना आवश्यक है, ताकि समावेशी और जिम्मेदार समाज का निर्माण किया जा सके। इस अवसर पर 3.2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। उपराष्ट्रपति ने डिजीलॉकर के माध्यम से प्रमाणपत्र जारी किए और इग्नू एलुमनाई पोर्टल का भी शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक तकनीक, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा और समाज के विकास में *–शेष पृष्ठ दो पर*

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी- जल्द खत्म हो सकती है पूरी सभ्यता

वॉशिंगटन (हि.स.)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि तय समयसीमा तक समझौता नहीं हुआ, तो आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। यह बयान ऐसे समय आया है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप ने ईरान को रात 8 बजे (ईस्टर्न टाइम) तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट खोलने और युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करने की बात कही गई है। उन्होंने साफ संकेत दिए कि समयसीमा पूरी होते ही अमेरिका बड़े सैन्य कदम उठा सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ईरान को डेडलाइन दी है। बीते कुछ हफ्तों में वे कई बार अलग-अलग समयसीमाएं तय कर चुके हैं। 21 मार्च को उन्होंने 48 घंटे में रास्ता खोलने की चेतावनी दी थी, जबकि 23 मार्च को बातचीत के चलते हमलों को अस्थायी रूप से टाल दिया गया। इसके बाद 27 मार्च को डेडलाइन बढ़ाकर 06 अप्रैल कर दी गई, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। फिर 03 अप्रैल को फिर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और 05 अप्रैल को *पावर प्लांट डे* और *ब्रिज डे* जैसे संकेतों के साथ ईरान के अहम ढांचों पर हमले की चेतावनी दी गई। अब 07 अप्रैल को ट्रंप का यह ताजा बयान अब तक का सबसे सख्त माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका जताई है। उधर ईरान में तेजी से बदलती स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक इस समय ईरान में हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जहां हैं वहीं रहें। सुरक्षित जगह पर पनाह लें और कहीं भी आने-जाने से बचें। अगले 48 घंटे तक घर में ही रहें। कहीं भी आने-जाने से पहले भारतीय दूतावास से संपर्क कर लें। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन से पहले अमेरिका ने ईरान पर हमले करना शुरू कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खर्ग आइलैंड और रेल नेटवर्क को निशाना बनाया। हमले के बाद ईरान के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गए। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो पर ऐसा होगा। ट्रंप ने कहा कि ये इतिहास के सबसे अहम पलों में एक होगा। भगवान ईरान के लोगों की रक्षा करें। ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी धमकी है। उन्होंने कहा है कि आज रात आर्थिक आतंकवाद खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान आर्थिक आतंकवाद फैला रहा है। अमेरिका-इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी हमले किए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तेल और गैस फील्ड पर हमला किया। इसके अलावा अमेरिका के सहयोगी देशों के भी गैस और ऑयल फील्ड को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइली मिलिट्री फैसलिटी पर भी हवाई हमला किया। ट्रंप ने सोमवार को ईरान को बड़ी धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान मंगलवार रात 8 बजे तक (अमेरिकी समय के मुताबिक) होर्मुज नहीं खोला तो वो ईरान को तबाह कर देंगे।

धर्म के लिए लड़ने वाला कभी नहीं मरता : भागवत

मथुरा (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत ने धर्म के लिए लड़ने वाला कभी मरता नहीं है। अधर्मी को मार देता है और अपनी सत्ता वापस लेता है। अब समय आ गया है कि भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व को नई सुखी और सुंदर दुनिया के बनाएगा। इसके लिए संतों से संतत्व से सीख लेकर उनकी प्रेरणा और अध्यात्म के आधार पर भारत विश्व गुरु बनेगा। इसके लिए संघ संतों के साथ मिलकर प्रयास करेगा। हम अपने अंदर का भाव बदलें, देश खुद ही बदल जाएगा। संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत मंगलवार को वृंदावन स्थित मलूकपीठ आश्रम में संत मलूकदास महाराज के 452वें जयंती महोत्सव का योग गुरु बाबा रामदेव के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने संत शिरोमणि मलूकदास महाराज की समाधि पर पूजा-अर्चना की और वहां की पवित्र रज को माथे से लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जगद्गुरु संत मलूकदास की 452वीं जयंती महोत्सव में शाम के समय शामिल हुए। डॉ भागवत ने कहा कि हम जगद्गुरु मलूकदास का 452वां जयंती उत्सव मना रहे हैं। हमारे सामने उनका जीवन एक प्रेरणा के समान है। उन्होंने अपने जीवन से हमें संदेश दिया। संत हमारे सामने सशरीर दिखाई देते हैं, लेकिन संत हमारे कल्याण के लिए जीवन जीते हैं। संत हमेशा से धर्म के लिए लड़े और मरे भी हैं। डॉ भागवत ने कहा कि धर्म के लिए लड़ने वाला कभी मरता नहीं है। अधर्मी को मार देता है और अपनी सत्ता वापस लेता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व को नई सुखी और सुंदर दुनिया के बनाएगा। इसके लिए संतों से संतत्व से सीख लेकर उनकी प्रेरणा और अध्यात्म के आधार पर भारत विश्व गुरु बनेगा। इसके लिए संघ संतों के साथ मिलकर प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष सबको प्रकाशित करे, इसकी आवश्यकता है। अपनी आध्यात्मिक परंपरा के आधार पर रीति और नीति ऐसी होनी चाहिए। सत्य के आधार पर जीवन खड़ा होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सत्य, करुणा के बिना धर्म नहीं हो सकता। सबको मिलकर रहना चाहिए। करुणा जीवन में तब आती है, जब सबका दुख अपना दुख लगता है। देश के 142 करोड़ लोग संतत्व को प्राप्त होगा यह संभव नहीं है, लेकिन सभी का सुचिता पूर्ण जीवन हो इसके लिए प्रयास करना है। महंत राजेंद्र दास महाराज की गौहत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध करने की मांग पर उन्होंने कहा कि समाज को गौभक्त बनाओ, गौहत्या अपने आप रुक जाएगी। लोगों को इसके लिए सामर्थ्यवान बनाओ। यह एक साहसी कदम होगा। जब गौ हत्या के विरोध में देश में जनभावना खड़ी हो गई तो सरकार को यह मानना होगा।

ऊपरी असम में क्लीन स्वीप करेगा एनडीए : सीएम

जोरहाट (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व वाला गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में ऊपरी असम में क्लीन स्वीप करेगा और कुल 95 से 100 सीटें हासिल करेगा। उन्होंने यह बयान प्रचार के अंतिम दिन टियोक में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस मौके पर अखिल गोगोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निचले असम से *मियां-मुस्लिम* समुदाय को ऊपरी असम में लाकर भविष्य का वोट बैंक तैयार करने की *खतरनाक साजिश* रची जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के समय जिस तरह की रणनीति अपनाई गई थी, उसी तरह की कोशिशें अब की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह कदम रोजगार सृजन के लिए नहीं, बल्कि केवल वोट बैंक की राजनीति के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अखिल गोगोई से सवाल किया कि दो बार के विधायक कुशल दुवरी के शिवसागर से चुनाव लड़ने पर क्या वे अचानक *बुरे व्यक्ति* बन गए हैं? इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि गिरफ्तारी के डर से वे दिल्ली से हैदराबाद चले गए।

कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के लिए जारी किया घोषणापत्र

कोलकाता (हि.स.)। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी करते हुए राज्य की जनता के समक्ष *नेहरूवादी मध्य मार्ग* को तीसरे विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में यह चुनावी घोषणापत्र जारी किया। इस अवसर पर खड़गे ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पिछले 20 वर्षों में पहली बार बंगाल में अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों से राज्य भ्रष्टाचार और नियंत्रण की राजनीति में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल ध्रुवीकरण, घृणा और हिंसा की राजनीति कर रही है, जिससे बंगाल का आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। कांग्रेस के घोषणापत्र में बंगाल की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने याद दिलाया कि कोलकाता कभी निवेश का प्रमुख गंतव्य था, लेकिन आज यहां के युवाओं को रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों का रुख करना पड़ रहा है।

दिल्ली विधानसभा सुरक्षा चूक पर सरकार सख्त

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक पर मंगलवार को लेकर हाई-लेवल मीटिंग हुई है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। यह सतर्कता, स्पष्ट जिम्मेदारी और बेहतर समन्वय पर आधारित होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को अपने कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बीच घटनाक्रम की विस्तार से समीक्षा की गई, जिसमें उपलब्ध फुटेज भी शामिल है जो तकनीकी जांच के अधीन है। विधानसभा अध्यक्ष ने आरोपी की पहचान करने और उसे तुरंत गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने विधानसभा परिसर में हुई सुरक्षा चूक को गंभीर बताते हुए कहा कि कम समय में घटी इस घटना ने, जिसमें अध्यक्ष के वाहन सहित आधिकारिक आवाजाही प्रभावित हुई, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। गुप्ता ने सभी प्रवेश द्वारों पर हाइड्रोलिक रोड ब्लॉकर्स लगाने, प्रवेश नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और परिसर के भीतर अधिक प्रभावी एवं त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तैयारी के साथ-साथ जवाबदेही भी जरूरी है। उन्होंने सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के बीच एक एकीकृत कमान (सिंगल पॉइंट ऑफ अथॉरिटी) बनाने पर जोर दिया ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। उन्होंने सभी एजेंसियों को रीयल-टाइम में सूचना साझा करने का निर्देश दिया। प्रवेश व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर सख्त नियंत्रण, बेहतर निगरानी और मजबूत बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गेट पर दिल्ली पुलिस/सीआरपीएफ के कम से कम दो प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती हो, जिन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय हों, ताकि समन्वित सतर्कता बनी रहे। अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना उचित सुरक्षा जांच और अनुमति के किसी भी वाहन को किसी भी स्थिति में परिसर में प्रवेश न दिया जाए। विधानसभा परिसर में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष ने एक मोबाइल पेट्रोलिंग वाहन तैनात करने का निर्देश दिया, जो तेजी से घूमकर तुरंत कार्रवाई कर सके और अनधिकृत गतिविधियों को रोक सके। उन्होंने कहा कि केवल स्थिर तैनाती पर्याप्त नहीं है, सुरक्षा में गतिशीलता भी जरूरी है। उन्होंने प्रवेश द्वारों की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि गेट इतने मजबूत हों कि जबरन प्रवेश को रोक सकें। इसके लिए सभी गेटों पर हाइड्रोलिक रोड ब्लॉकर्स और अन्य सुदृढ़ीकरण उपाय लागू करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा को निरंतर प्रक्रिया बताते हुए गुप्ता ने नियमित समीक्षा बैठक, सभी अवलोकनों का रिकॉर्ड रखने और समय पर सुधारात्मक कदम उठाने की बात कही। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी लोगों और वाहनों की पूरी जांच अनिवार्य है। इसके अलावा, संयुक्त निदेशक, खुफिया ब्यूरो, नवीन वर्मा ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विधान सभा परिसर का मुआयना करने के साथ विस्तृत समीक्षा की और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक मूल्यांकन किया। टीम ने घटनाक्रम का बारीकी से निरीक्षण किया और प्रवेश प्रबंधन और जमीनी प्रतिक्रिया को और मजबूत करने की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की।

पृष्ठ एक का शेष

असम विस चुनाव : प्रचार...

पार्टी ने दो सीटों, राइजर दल ने 13 सीटों, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने 10 सीटों, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) ने चार सीटों, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट) ने एक सीट, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) ने 41 सीटों, द नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया ने दो सीटों, विकास इंडिया पार्टी ने पांच सीटों और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 16वीं असम विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में 258 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। असम की 126 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 50 लाख 21 हजार 413 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 25 लाख 16 हजार 591 है, महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 25 लाख 4 हजार 501 है और तीसरे लिंग के मतदाता 321 हैं। इसके अलावा, असम के मतदाता सूची में नए तरीके से 1 लाख 64 हजार 48 लोगों को शामिल किया गया है और 1 लाख 774 लोगों का नाम हटाया गया है। दूसरी ओर, असम में 18-19 वर्ष आयु के मतदाताओं की संख्या 6 लाख 28 हजार 93 है, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 1 लाख 2 हजार 472 हैं और 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 2 हजार 482 है। इसके अतिरिक्त, राज्य का सबसे अधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र दलगांव है। यहां 3 लाख 17 हजार 110 मतदाता हैं। इसके विपरीत, असम का सबसे कम मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र आमरी है। यहां 1 लाख 494 मतदाता हैं। इसके लिए असम में विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन कुल 31 हजार 486 मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान करके आने वाले पांच वर्षों के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। चुनावों को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा बलों की लगभग 200 कंपनियां तैनात की गयी हैं। राज्य और जिला सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और चुनाव अवधि के दौरान सीसीटीवी निगरानी का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग के डाटा के अनुसार, राज्य में कुल 31,486 पोलिंग स्टेशन बनाए गये हैं। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 27,711 और शहरी क्षेत्र में 3,775 हैं। महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 3,716 है। वहीं मॉडल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 126 है। चुनाव आयोग के अनुसार शत-प्रतिशत वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गयी है। मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के द्वारा सभी तरह के आवश्यक इंतजाम किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) गठबंधन 76 सीटें जीती थीं। इनमें भाजपा ने 60, असम गण परिषद ने 9 और यूपीपीएल ने 6 सीटें व एक अन्य ने जीती थीं। दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन 49 सीटें जीती थीं। इनमें कांग्रेस ने 29, एआईयूडीएफ ने 16 और सीपीआई (एम) ने एक सीट और चार सीटें निर्दलीय समेत अन्य ने जीती थीं।

मणिपुर में धमाका...

लिए दृढ़ संकल्पित है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी कि शांति-व्यवस्था और स्थिरता को कोई खतरा नहीं पहुंचे। वहीं, स्थानीय एनपीपी विधायक शांति सिंह ने ट्रोंग्लाओबी में कुकी नार्को-उग्रवादियों पर इस क्रूर हमले का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद स्थानीय भाजपा विधायक टीएच शांति सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे बेहद क्रूर और अमानवीय कृत्य बताया। विधायक ने कहा कि यह हमला आतंकवाद से कम नहीं है और समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमले में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इतने छोटे और मासूम बच्चों की इस तरह हत्या होना बेहद दुखद और निंदनीय है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की।

असम भाजपा ने खड़गे ...

गई बेहद आपत्तिजनक और गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है, जो हिंदू आस्था और परंपरा का सरासर अपमान है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान ने केवल निंदनीय हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव के लिए खतरनाक भी हैं। कलिता ने यह भी आरोप लगाया, कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए जानबूझकर सनातन संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जब अन्य धर्मों को श्रेष्ठ के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने दावा किया, असम की जनता और पूरे देश ने इस विभाजनकारी नजरिये को पहले ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, इस भड़काऊ और विभाजनकारी बयानबाजी का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए असम भाजपा ने गुवाहाटी के वशिष्ठ थाने में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कराई है। असम राज्य चुनाव आयोग को भी एक शिकायत दी गई है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव अभियान के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ और समाज को बांटने वाले बयान फैलाने के आरोप में खड़गे के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है। राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए नौ अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना चार मई को होगी।

पवन खेड़ा पर असम ...

रखने और संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। उन्होंने इन आरोपों के समर्थन में कथित दस्तावेज भी दिखाए थे। खेड़ा ने चुनाव आयोग से शर्मा का नामांकन रद्द करने की मांग की थी। शर्मा ने इन दावों को दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया था। उन्होंने 48 घंटे के भीतर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। कांग्रेस ने 6 अप्रैल को चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें शर्मा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई है। कांग्रेस का तर्क है कि शर्मा ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी की कथित विदेशी संपत्तियों का उल्लेख नहीं किया है।

विस चुनाव खत्म होते ...

कर्नाटक जैसे 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। 19 फरवरी को ही चुनाव आयोग ने इन राज्यों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दे दिए थे। यह अभियान केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस पर सियासी बवाल भी खूब हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट में निजी तौर पर पक्ष भी रखा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस अभियान के जरिए ऐसे मतदाताओं को निशाना बनाया जा सकता है जो सत्ताधारी दल के समर्थक नहीं हैं। इससे पहले बिहार में अभियान के दौरान आयोग के अधिकारियों ने दावा किया था कि बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के कई नागरिक मतदाता सूची में पाए गए हैं। हालांकि, बाद में इसका कोई पुख्ता आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। इस *विशेष गहन पुनरीक्षण* का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से फर्जी नामों, तस्वीरों की गड़बड़ियों, मृतकों के नाम और एक से ज्यादा जगह दर्ज नामों को हटाना है। अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में दिल्ली समेत अन्य राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर सत्यापन कर सकते हैं।

हैट्रिक की राह में ...

भारतीय जनता पार्टी राज्य में विकास की बात जोर-शोर से कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं, जिनकी ओर विपक्षी पार्टियों के जोरदार अपील करने पर हार-जीत का मामला 50-50 हो सकता है। जरूर चीजों के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। जोकि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहे हैं। ऐसे में यह मुद्दा चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ असम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य में खाद्य महंगाई में तेज वृद्धि देखने को मिली है। जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मतदाता प्रभावित हैं। राज्य के अन्य सियासी दल महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। जिसको सत्ता विरोधी लहर के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सत्ताधारी दल ने आरोपों को सिरों से खारिज कर दिया है और अपनी *विकास परियोजनाओं* पर ध्यान केंद्रित किया है।

आरएसएस मुख्यालय के ...

और फॉरेंसिक टीम ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और तलाशी ली और विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक, यह विस्फोटक पिछले एक से डेढ़ महीने से यहां रखे होने की आशंका है। शुरुआती जांच में इनका कनेक्शन हाल ही में काटोल क्षेत्र में हुई विस्फोटक कंपनी हादसे से जुड़ने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। इलाके में करीब 200 मीटर पर जामा मस्जिद, 500 मीटर पर पोद्दारेश्वर राम मंदिर और डेढ़ से दो किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मुख्यालय स्थित है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। नागपुर के सह पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि गार्डन में विस्फोटक किसने रखा, इसके पीछे क्या मंशा थी और इनका इस्तेमाल कहां होना था इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में पुलिसबल तैनात है और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है।

कोलकाता पर हमला ...

राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उस युद्ध के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया था और बांग्लादेश का गठन हुआ था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान इस बार पश्चिम बंगाल की ओर बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा तो इस बार उसके कितने टुकड़े होंगे, यह केवल भगवान ही जानते हैं। क्या कहा था पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नेपाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 04 अप्रैल को सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि भारत कोई झूठा हमला (फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन) करने की कोशिश करता है तो संघर्ष केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। उनके इस बयान के बाद भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका सार्वजनिक रूप से जवाब दिया।राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को इतिहास से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि 55 वर्ष पहले 1971 में जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े थे। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान ने फिर कोई दुस्साहस किया तो परिणाम और भी अधिक गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को उकसाने वाली बयानबाजी से बचने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की दिशा में काम करने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब पाकिस्तान कोलकाता पर हमले की बात करता है तब केंद्र सरकार को स्पष्ट प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में तो पश्चिम बंगाल की आलोचना करते हैं, लेकिन बाहरी धमकियों पर चुप रहते हैं। ममता सरकार पर राजनाथ सिंह का निशानाअपने भाषण में राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में *उत्पीड़न* और *विश्वासघात* की राजनीति हुई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के तीन कार्यकाल के दौरान राज्य की आर्थिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां देश के अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में निवेश का माहौल कमजोर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई उद्योग राज्य से बाहर चले गए हैं और नए निवेशक भी यहां आने से हिचकिचा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नारे *बांग्ला निजेर मेयेकेई छाय* (बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है) का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जनता ने तीन बार अपनी *बेटी* को चुना, लेकिन बदले में उन्हें विश्वासघात मिला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तीन बार मुख्यमंत्री बनीं लेकिन राज्य की जनता को अपेक्षित विकास नहीं मिल पाया।

घुसपैठियों के बाहर ...

व्यक्ति भी वोटर सूची में शामिल हो जाते हैं। इससे न केवल चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती थी बल्कि असली मतदाताओं का अधिकार भी कमजोर होता था। एसआईआर ने इसी कमजोरी पर सीधा प्रहार किया है। आंकड़े खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। फरवरी तक ही साठ लाख से अधिक नामों की पहचान कर उन्हें जांच के दायरे में लाया गया। बाद में गहन जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद करीब सत्ताईस लाख नामों को हटाया गया, जबकि जिन लोगों के दस्तावेज सही पाए गए उन्हें सूची में बरकरार रखा गया। यह दिखाता है कि प्रक्रिया मनमानी नहीं बल्कि ठोस आधार पर हुई है। तार्किक विसंगति श्रेणी में रखे गए मामलों पर खास ध्यान दिया गया। करीब पैंतालीस प्रतिशत मामलों में नाम हटाने का फैसला इस बात का संकेत है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग सूची में शामिल थे जिनकी पात्रता संदिग्ध थी। अगर यह प्रक्रिया नहीं होती तो यही लोग चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते थे। सबसे अहम बात यह है कि पूरी प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में हुई। उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने हर मामले की सुनवाई की। अपील के लिए अलग से न्यायाधिकरण बनाए गए हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार चुनाव आयोग ने केवल सूची संशोधन नहीं किया, बल्कि चुनावी व्यवस्था को साफ करने का बड़ा अभियान चलाया है। जिला स्तर पर आंकड़े सार्वजनिक किए गए, हर चरण को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई और प्रक्रिया को नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया गया। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में जहां सबसे अधिक संदिग्ध मामले सामने आए, वहां विशेष सतर्कता बरती गई। यह वही इलाके हैं जहां लंबे समय से घुसपैठ को लेकर चर्चा होती रही है। अब पहली बार इन इलाकों में भी सख्त कार्रवाई का असर दिख रहा है। मतदान की तारीखें तय हैं और पहले चरण की मतदाता सूची अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि अब किसी भी तरह की हेरफेर की गुंजाइश नहीं बची है। जो नाम सूची में हैं, वही मतदान करेंगे और जो हटाए गए हैं, वह इस बार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। यह फैसला भले कुछ लोगों को कठोर लगे, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी था। अगर मतदाता सूची में ही गड़बड़ी हो तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एसआईआर ने इस बुनियादी समस्या को दूर करने का काम किया है। इस दौरान तकनीकी चुनौतियां जरूर आईं, जैसे डिजिटल हस्ताक्षर में देरी या आदेश अपलोड करने में समस्या, लेकिन इन सबके बावजूद प्रक्रिया को समय सीमा में पूरा करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यह दिखाता है कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, वे यही बताते हैं कि प्रक्रिया नियमों के अनुरूप और व्यवस्थित ढंग से पूरी की गई है। आगे भी अगर कोई सुधार की जरूरत होगी तो वह कानूनी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव केवल संख्या का खेल नहीं रहेगा, बल्कि यह वास्तविक मतदाताओं की भागीदारी का उत्सव बनेगा। दशकों बाद ऐसा मौका आया है जब घुसपैठ या अपात्रता के आरोपों से परे जाकर चुनाव कराए जा रहे हैं। बहरहाल, यह बदलाव केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। अगर इसी तरह मतदाता सूची को शुद्ध किया जाए तो लोकतंत्र और मजबूत होगा और जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल अब एक नए चुनावी अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां मतदाता सूची पर भरोसा ज्यादा मजबूत है और प्रक्रिया ज्यादा सख्त। यही इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी कहानी है।

आधुनिक विकास को ...

महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसके नैतिक मूल्य हैं और विकास की दिशा में आगे बढ़ते समय परंपराओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वैज्ञानिक उन्नति को नैतिकता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाना समय की मांग है। उपराष्ट्रपति ने इग्नू की भूमिका की सराहना करते हुए इसे देश में समावेशी और सुलभ उच्च शिक्षा का मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाकर सामाजिक समानता और अवसरों का विस्तार किया है। उन्होंने बताया कि इग्नू में 14 लाख से अधिक शिक्षार्थी हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों की है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का सशक्त उदाहरण है। कोविड-19 महामारी के दौरान इग्नू ने स्वयं और ई-ज्ञानकोष जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा को निर्बाध जारी रखा। उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और मल्टीपल एग्जिट विकल्पों को शिक्षा प्रणाली में लचीलापन लाने वाला कदम बताया। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, इग्नू की कुलपति प्रो. उमा कंजीलाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

असम में भूकंप के ...

की गहराई में स्थित था। भूकंप का एपिसेंटर 24.823 उत्तरी अक्षांश और 92.634 पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया। झटके महसूस होते ही लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

कर्नाटक में कई अधिकारियों ...

छापा मारा। एसपी वासुदेव राम और डीवाईएसपी मृत्युंजय के नेतृत्व में सुशीलम्मा के ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। लोकायुक्त की एक टीम ने बल्लारी शहर में मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक शिवन्ना के घर और उनके कार्यालय सहित चार स्थानों पर छापा मारा। उनके सिद्धार्थ नगर स्थित आवास में लोकायुक्त के अधिकारी बैंक दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा शिवमोग्गा जिले में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिला अधिकारी शोभा के कार्यालय और उनके आवास पर भी छापा मारा गया। शिकारीपुर के पास तरलघट्टा, सागर तालुक के आनंदपुर क्षेत्र सहित कई स्थानों पर एक साथ जांच की गई। बेलगावी जिले में शहरी विकास प्रकोष्ठ के एईई अजय सिंह राजपूत के अंजनेय नगर, अथानी और हुक्केरी सहित तीन स्थानों ठिकानों पर भी छापे डाले गए है। इसी तरह मांड्या जिले में लोक निर्माण विभाग के एईई रेवन्ना के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में कार्रवाई की गई। मैसूर स्थित कार्यालय और मांड्या के निवास पर दस्तावेजों की जांच चल रही है। इन सभी कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शांति लौटने के बाद विकास के पथ पर अग्रसर असम : अमित शाह

हैलाकांदी (हि.स.)। आसन्न असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अंतिम चरण के प्रचार के दौरान बराक घाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में असम में शांति वापस आई है और राज्य अब तेज गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को बराक घाटी के तीन जिलों श्रीभूमि, हैलाकांदी और सिलचर में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। श्रीभूमि जिला के पथारकांदी में भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल, हैलाकांदी में भाजपा उम्मीदवार डॉ. मिलन दास के समर्थन में सभा में शामिल हुए। उसके बाद वे सिलचर में डॉ. राजदीप रॉय और उदारबंद सीट से राजदीप गोवाला के पक्ष में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनसभाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और भाजपा सरकार के दौरान राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि असम को देश के अन्य विकसित राज्यों की तरह आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले पांच वर्षों में इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने भूमि पट्टा वितरण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और श्रीभूमि में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया है। साथ ही, आने वाले समय में राज्य के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं तैयार की गई हैं। अमित शाह ने सिलचर के विकास पर विशेष जोर देते हुए कहा कि गुवाहाटी की दूरी को देखते हुए सिलचर को ही एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिए गुवाहाटी जाने की आवश्यकता न पड़े। इसके अलावा किसानों के लिए भी विभिन्न सुविधाएं और योजनाएं लागू की जाएंगी।

कार्बी आंग्लांग पहाड़ी जिले के दूरस्थ पोलिंग स्टेशनों के लिए 21 पोलिंग टीमें दो दिन पहले रवाना

कार्बी आंग्लांग (हि.स.)। असम के पहाड़ी जिले कार्बी आंग्लांग में आगामी (09 अप्रैल) को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में स्थित 21 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग टीमें मंगलवार को डिफू गवर्नमेंट कॉलेज से अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गईं। मतदान से दो दिन पहले ही इन टीमों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, ताकि समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा सकें। पोलिंग टीमों को रवाना करते हुए जिला चुनाव अधिकारी अरण्यक सैकिया ने उनके सुरक्षित सफर और सफल दायित्व निर्वहन की कामना की। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद पोलिंग कर्मचारियों का समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मजबूत नींव है। उन्होंने कर्मचारियों को लोकतंत्र का आधार बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत से हर पात्र मतदाता अपने मतदान अधिकार का उपयोग कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि ये 21 मतदान केंद्र बोकाजान विधानसभा क्षेत्र नंबर 108, हावराघाट विधानसभा क्षेत्र नंबर 109 और डिफू विधानसभा क्षेत्र नंबर 110 के हैं। इन पोलिंग स्टेशनों पर कुल 11,021 मतदाता हैं। इनमें से 5,619 पुरुष और 5,402 महिला शामिल हैं। बोकाजान विधानसभा क्षेत्र नंबर 108 के तहत आठ (8) मतदान केंद्रों पर 3,483 मतदाता, हावराघाट विधानसभा क्षेत्र नंबर 109 के तहत 10 मतदान केंद्रो पर 6,468 मतदाता और डिफू विधानसभा क्षेत्र नंबर 110 के जवलियां इलाके में तीन (3) मतदान केंद्रों पर 1,070 मतदाता हैं। ये सभी मतदान केंद्र दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण है। सामान्य परिस्थितियों में भी कई स्थानों तक केवल चार पहिया वाहनों से ही पहुंचा जा सकता है, जबकि बारिश के मौसम में रास्ते पूरी तरह अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे हालात में पोलिंग कर्मियों को कई बार लंबी दूरी तक पैदल चलकर अपने केंद्रों तक पहुंचना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

रिनिकी भुइयां शर्मा का जालुकबाड़ी में मैराथन चुनाव प्रचार

गुवाहाटी (हि.स.)। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा ने जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में व्यापक और मैराथन चुनाव प्रचार किया। वे देर रात तक क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जाकर मतदाताओं से संपर्क साधती रहीं। प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की और क्षेत्र के विकास तथा जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। उनके इस लगातार वार्ड-वार्ड दौरे को जमीनी स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने की एक अहम कोशिश माना जा रहा है। इससे पहले वार्ड संख्या 8 में स्थित कामाख्या मंदिर के समीप आयोजित एक सभा में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। सभा में लोगों की भारी उपस्थिति से चुनावी माहौल में बढ़ती सक्रियता साफ नजर आई।

गुवाहाटी के बामुनीमैदाम में भीषण आगजनी, कई घर खाक

गुवाहाटी (हि.स.)। गुवाहाटी के बामुनीमैदाम इलाके में स्थित अनुराधा रेलवे कॉलोनी में बीती देर रात अचानक भीषण आग की घटना सामने आई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सिलेंडर विस्फोट के कारण आग लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूत्रों के मुताबिक एक साथ करीब सात सिलेंडरों के फटने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में लगभग 50 से 60 घर जलकर खाक हो गए हैं, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गईं। रेलवे कॉलोनी में इस समय भय और हाहाकार का माहौल बना हुआ है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है।

हाफलांग विस के दूरस्थ पोलिंग बूथों के लिए मतदान कर्मी रवाना

हाफलांग (हि.स.)। असम विधानसभा चुनाव के लिए अब महज दो दिन शेष रह गए हैं। राज्य में 9 अप्रैल को एक ही चरण में सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आमतौर पर मतदान कर्मी चुनाव से एक दिन पहले चुनाव सामग्री के साथ अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना होते हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इस बार कुछ स्थानों पर विशेष व्यवस्था की गई है। आदिवासी आरक्षित 113 हाफलांग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दूर-दराज के इलाकों के लिए मतदान कर्मियों को मंगलवार को ही रवाना कर दिया गया। डिमा हसाओ जिले के जिला चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार, जिनम वैली पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए हाफलांग से सिलचर और फिर हरिनगर होते हुए लंबा सफर तय करना पड़ता है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मतदान कर्मियों को समय से पहले भेजा गया है, ताकि वे सुरक्षित और समय पर अपने निर्धारित केंद्रों तक पहुंच सकें। इन कर्मियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और अन्य जरूरी चुनावी सामग्री के साथ रवाना किया गया है। चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार, शेष पोलिंग स्टेशनों के लिए मतदान कर्मी 8 अप्रैल को अपने-अपने केंद्रों के लिए प्रस्थान करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा सभी व्यवस्थाओं को लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।

रिनिकी भुइयां के कथित पासपोर्ट मामले में कांग्रेस के आरोप निराधार, सभी दस्तावेज फर्जी : मार्घेरिटा

गुवाहाटी (हि.स.)। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्घेरिटा ने मंगलवार को कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के नाम पर प्रस्तुत किए गए सभी पासपोर्ट पूरी तरह से फर्जी हैं और उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मार्घेरिटा ने कहा कि भारत सरकार ने आधिकारिक जांच के बाद कांग्रेस द्वारा दिखाए गए सभी दस्तावेजों को फर्जी घोषित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिनिकी भुइयां शर्मा के संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और एंटीगुआ और बारबुडा के पासपोर्ट होने के दावे पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। मार्घेरिटा ने बताया कि उक्त देशों की सरकारों ने भी औपचारिक रूप से भारत सरकार को सूचित किया है कि संबंधित पासपोर्ट असली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच आधिकारिक माध्यमों से की जा चुकी है और इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं पाई गई है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के भ्रामक आरोप केवल जनता को गुमराह करने के लिए लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हर मुद्दे की जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोकराझाड़ में चुनाव तैयारियों का विशेष पर्यवेक्षक ने की समीक्षा

कोकराझाड़ (हि.स.)। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष पर्यवेक्षक मनजीत सिंह ने मंगलवार को कोकराझाड़ जिले के सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। मतदान केंद्रों के दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समग्र तैयारियों का आकलन किया। इस दौरान कोकराझाड़ के डिप्टी कमिश्नर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा पी उदय प्रवीण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अक्षत गर्ग तथा जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष पर्यवेक्षक के साथ मौजूद रहे और जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा लिया। इसके पश्चात विशेष पर्यवेक्षक ने जिला आयुक्त कार्यालय, कोकराझाड़ में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सामान्य पर्यवेक्षक, व्यय पर्यवेक्षक तथा पुलिस पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा की गई, आपसी समन्वय को और मजबूत करने पर जोर दिया गया तथा चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

कोकराझाड़ में थमा चुनाव प्रचार, कल पांच सीटों पर होगा मतदान

कोकराझाड़। कोकराझाड़ जिले के पांच महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों—बउखूंगारी, कोकराझाड़, परबतझोरा, दोतामा और गोसाईगांव—में अंतिम चरण का चुनावी शोर आज थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। प्रचार के अंतिम घंटों में बीपीएफ, यूपीपीएल, कांग्रेस, टीएमसी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी। क्षेत्र में जगह-जगह रैलियां, रोड शो और जनसभाओं का आयोजन किया गया। उम्मीदवारों ने घर-घर जाकर विकास, सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों के नाम पर वोट मांगे। विशेष रूप से बीपीएफ और यूपीपीएल के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है, जबकि कांग्रेस और टीएमसी ने भी त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा कर दी है। ?जिले की इन पांचों सीटों पर आगामी 9 अप्रैल को मतदान होना है। प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। ?9 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी की निगाहें 4 मई पर टिकी रहेंगी, जब मतगणना होगी और यह साफ होगा कि कोकराझाड़ की जनता ने अपना प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी है। फिलहाल, सभी दलों के नेता अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन असली फैसला जनता के हाथ में है।

होजाई में प्रचार का अंतिम दिन कांग्रेस-भाजपा का शक्ति प्रदर्शन

होजाई। असम विधानसभा चुनाव के दो दिन शेष रहते होजाई में कांग्रेस और भाजपा ने अंतिम प्रचार के दिन विशाल बाइक रैलियों से चुनावी माहौल को गरमा दिया। निर्वाचन नियम के अनुसार प्रचार आज सायं पांच बजे समाप्त हो गया। कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार झिल्ली चौधरी ने सुबह से शहर की गलियों से शुरू कर गांव-गांव तक विशाल बाइक रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई। वहीं, भाजपा उम्मीदवार शिलादित्य देव ने कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर दो बजे होजाई के मैन रोड स्थित स्वामी विवेकानंद क्रीडांगन से प्रारंभ होकर शहर से ग्रामीण क्षेत्रों तक भव्य बाइक रैली आयोजित की, जिसमें जिला अध्यक्ष दिलीप धर साथ थे। दोनों दलों ने अंतिम क्षणों में वोटरों का मन जीतने की पूरी कोशिश की। नौ अप्रैल को होने वाले मतदान के परिणाम चार मई को घोषित होंगे, तब तक यह तय होगा कि कौन सा दल कितने प्रतिशत वोट हासिल कर विजयी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवार शिलादित्य देव की लोकप्रियता और अपेक्षाएं अधिक दिखीं, जबकि कांग्रेस की झिल्ली चौधरी ने प्रचार में कहीं पीछे नहीं हटी। वोटरों के बीच दोनों की बराबरी की टक्कर है। अब मतगणना के पश्चात ही पता चलेगा कि ताज किसके सर सजेगा ।।

चुनाव से पहले कछार में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त

कछार (हि.स.)। असम में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कछार जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में बीती रात गुमरा पुलिस ने मेघालय सीमा के दिगरखाल इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया है। पुलिस ने मेघालय से मिजोरम की ओर जा रहे सीमेंट लदे दो ट्रकों को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रकों में सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपाकर रखे गए 401 कार्टून इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) बरामद किए गए। दिगरखाल चेकगेट पर की गई इस कार्रवाई में विभिन्न ब्रांड की करीब 1,804 लीटर शराब जब्त की गई। जब्त शराब की बाजार कीमत कई लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान कलाइन भैरवपुर के असलम उद्दीन बरभुइया और फारुक इस्लाम, ब्राह्मणग्राम के जुनैद अहमद तथा नातुनपुर के दिलदार हुसैन के रूप में हुई है। यह जानकारी गुमरा पुलिस चौकी के प्रभारी प्रणव मिली ने मंगलवार को दी। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है।

पूसीरे ने कामाख्या डिपो में शुरू की वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए उन्नत तकनीकी प्रणाली

गुवाहाटी (हि.स.)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) ने नई पीढ़ी की वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए कामाख्या कोचिंग डिपो में अपने आप विकसित किए गए उन्नत तकनीकी उपकरणों की एक श्रृंखला शुरू करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पूसीरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने मंगलवार को बताया कि अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके और उन्नत वैश्विक मानकों का पालन करते हुए विकसित इन प्रणालियों में एक स्मार्ट एयर स्प्रिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, रियल-टाइम डायग्नोस्टिक्स के लिए एक पोर्टेबल वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, और स्वदेशी रूप से निर्मित एक बाहरी पिट पावर सप्लाई तथा प्री-कूलिंग सिस्टम शामिल हैं। कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस इस वर्ष जनवरी से कामाख्या और हावड़ा के बीच चल रही है, जिससे विश्व स्तरीय और आरामदायक रेल यात्रा के एक नए युग की शुरुआत हुई है। इसी क्रम में पूसीरे ने अत्याधुनिक और किफायती तकनीकों का उपयोग करते हुए इन-हाउस विकसित उन्नत रखरखाव प्रणालियां शुरू की हैं। उन्होंने बताया कि पूसीरे द्वारा नवीन और सुदृढ़ तरीकों से अपनी क्षमता को बढ़ाने और हाई-स्पीड और प्रीमियम ट्रेन सेवाओं के रखरखाव को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सभी अत्याधुनिक प्रणालियों से संरक्षा में वृद्धि हुई है। रखरखाव की दक्षता में सुधार होने के साथ-साथ यह प्रणालियां वंदे भारत स्लीपर कोचों के विश्वसनीय एवं उच्च-प्रदर्शन वाले परिचालन को भी सुनिश्चित करती हैं। सीपीआरओ ने बताया कि तकनीकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के तौर पर कोचों की स्मार्ट और स्थिति-आधारित निगरानी को संभव बनाने के लिए एक *एयर स्प्रिंग मॉनिटरिंग सिस्टम* लागू किया गया है। यह सिस्टम महत्वपूर्ण मापदंडों की लगातार ट्रैकिंग, किसी भी गड़बड़ी का समय से पहले पता लगाने और उन्नत ध्वनिक इमेजिंग तकनीकों के माध्यम से सटीक सत्यापन सुनिश्चित करता है। यह पूर्वानुमान-आधारित और डेटा-संचालित दृष्टिकोण परिचालन विश्वसनीयता को बढ़ाता है, सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करता है और यात्रियों के लिए एक सुगम, आरामदायक और बेहतरीन यात्रा अनुभव सुनिश्चित करता है। उन्होंने बताया कि अपनी तकनीकी क्षमताओं को और अधिक मजबूत करते हुए पूसीरे ने पहली बार वास्तविक समय पर रोलिंग स्टॉक की स्थिति की निगरानी के लिए एक पोर्टेबल वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम चालू किया है। वर्तमान में कामाख्या डिपो में वंदे भारत स्लीपर रेक के लिए प्रयुक्त हो रहा यह सिस्टम संभावित समस्याओं की शीघ्र पहचान करने तथा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाता है, जिससे खराब होने या विफल होने की संभावना कम होती है और यात्रियों को निर्बाध यात्रा का अनुभव सुनिश्चित होता है। सीपीआरओ के अनुसार, एक अन्य अग्रणी पहल के तहत, एक एक्सटर्नल पिट पावर सप्लाई और प्री-कूलिंग सिस्टम को स्वदेशी रूप से निर्मित और कारगर बनाया गया है, जो सुरक्षित और कुशल रखरखाव के तरीकों में नए मानक स्थापित कर रहा है। यह सिस्टम ओएचई शटडाउन के दौरान वंदे भारत स्लीपर कोचों के सुरक्षित रखरखाव को सक्षम बनाता है तथा यह एचवीएसी, लाइटिंग और डायग्नोस्टिक्स जैसे जरूरी ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करता है। इसके अलावा, यह मेनटेनेंस कर्मचारियों के लिए बिजली के झटकों के जोखिम को भी समाप्त करता है और रेक टर्नअराउंड समय को काफी कम कर देता है, जिससे यात्रियों के लिए उच्च गुणवत्ता और अच्छी तरह रखरखाव किए गए कोचों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

संपादकीय

जरूरतों तक विकास

विकास महज योजना नहीं, सतत प्रयास की निरंतरता है। योजनाएं तो हिमाचल में बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन विकास के बही खाते सच्चे और सार्थक तभी होते, जब उद्देश्यों के गुणात्मक फलक पर संभावनाएं संबोधित हों। ऐसे में हिमाचल सरकार के तीन साल बनाम आने वाले चुनाव के दो साल के बीच अब बहस के मसौदे बदल रहे हैं। हिमकेयर योजना पर सदन की बहस में इससे क्या फर्क पड़ेगा कि घोटाला कितने करोड़ का है, लेकिन इसकी निरंतरता में आई गिरावट का जिक्र जरूर होगा। कुछ इसी तरह आखिरी सालों में आ रही परिवहन निगम की नई बसों से यातायात में क्या अंतर आएगा, इसके बजाय जिक्र यह कि सदन में मुद्दे ने अपनी आवश्यकता बताई। हिमाचल अपने विकास के मामले में कहीं आवश्यकता से अधिक, तो कहीं निरंतरता में कमजोर रहा है। नए स्कूलों की परिधि में विकास की आवश्यकता को पहचाना ही नहीं गया, नतीजतन स्कूलों को डिनोटिफाई करने का सिलसिला जारी है। बीस मार्च की अधिसूचना के अनुसार राज्य में शून्य छात्र संख्या के 36 सरकारी स्कूल डिनोटिफाई हो गए। कुछ यही हाल कालेज, मेडिकल कालेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने से भी हुआ। सरकार एड़ी चोटी का प्रयास करते हुए मेडिकल कालेजों में सुविधाएं बढ़ा रही है, लेकिन चिकित्सा का मूल आधार डिस्पेंसरी से शुरू होता है। यही आवश्यकता निजी क्षेत्र की उपलब्धि बन जाती है। हिमाचली मरीज के समीप मेडिकल कालेज हमेशा खड़ा नहीं होगा, बल्कि चिकित्सकीय निकटता के लिए अब डिस्पेंसरी, सिविल, क्षेत्रीय व जोनल अस्पतालों में तत्परता चाहिए। निजी अस्पताल अपनी कोशिश को इतना भरोसेमंद बना देते हैं कि मरीज इस एहसास को अंगीकार कर लेता है। विकास में समय और सम सीमा में विकास के अर्थ को हिमाचल में समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए हिमाचल में पर्यटक सीजन शुरू है, तो इस समय को रेखांकित करने की तत्परता कहां है। सदन में बहस के दौरान हर विधायक किसी न किसी तरह के विकास, योजनाओं या परियोजनाओं पर केंद्रित रहा, लेकिन किसने पर्यटन के रथ पर बैठ कर विकास की योजनाओं को इंगित किया। हमारा दस्तूर अब विकास की खिचड़ी है, 'चाहे इसमें वास्तविक सामग्री हो या न हो। एक सरकार भवन बनाती रही, तो दूसरी के आने के बाद मालूम हुआ कि इनमें से हजार बेकार हैं, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां बनाती नहीं। धर्मशाला में एक दशक से बस स्टैंड का निर्माण प्रयासरत है, लेकिन बनता नहीं। यहां उस सतत प्रयास की तारीफ करें कि फिर भी एक स्वर्गीय नेता के नाम पूरा परिसर हो जाता है। इसी धर्मशाला में प्रदेश के पहले ट्यूलिप गार्डन के प्रस्ताव में दस करोड़ के करीब खर्च हो जाते, लेकिन आज तक एक भी फूल खिला नहीं। कान्वेंशन सेंटर देगची पर चढ़ी खिचड़ी हो गया, तो विकास से पहले जहां सींग उगते हैं, उन परियोजनाओं पर रहम कौन करेगा। हम किसी भाजपा के विधायक से सुनेंगे, तो विकास गुजरे जमाने की दास्तान है और सत्तारूढ़ दल के विधायक बताते रहेंगे कि कितने कोस चल चुके हैं। हमने स्मार्ट सिटी के तहत शिमला-धर्मशाला की जागीर खोद दी। शिमला के शृंगार में लोहे का इस्तेमाल किसके आंचल में छेद कर रहा है, यह देखने की फुर्सत नहीं। धर्मशाला के स्मार्ट रोड के डक्ट में बहती गंदगी, एक नया अवतार है। आश्चर्य यह कि कहीं भवनों पर पेड़ उगे हैं, तो कहीं मिट्टी के ढेर लगे हैं। विकास की पैमाइश में ठेकेदारी प्रथा बदल गई। अधूरी संरचना, मलबे के ढेर और बिलों के भुगतान से खतरा यह कि निर्माण अब दर्द देता है। नगर निगम तो बढ़ गए, लेकिन शहरी जरूरतों के खाके में न सपने हैं और न ही सपनों को पूरा करने का बंदोबस्त। बेशक कारवां बड़ा हो गया, लेकिन मंजिल का पता नहीं। हमें यह पता है कि विकास के उच्चारण में कुछ ईंटें उठा लो, भले ही जरूरत का इंतजाम हो या न हो। हिमाचल के कितने सरकारी कार्यालयों के पास मुकम्मल पार्किंग सुविधा है और अगर नहीं है, तो हमारी योजना क्या है। कितने गांवों से शहरों तक हमें सामुदायिक मैदान चाहिएं, लेकिन हमारी योजना कहां है। जरूरतें जहां चीख रही हैं, वहां हमारे विकास का इंतजाम नहीं।

योजनाएं तो हिमाचल में बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन विकास के बही खाते सच्चे और सार्थक तभी होते, जब उद्देश्यों के गुणात्मक फलक पर संभावनाएं संबोधित हों। ऐसे में हिमाचल सरकार के तीन साल बनाम आने वाले चुनाव के दो साल के बीच अब बहस के मसौदे बदल रहे हैं। हिमकेयर योजना पर सदन की बहस में इससे क्या फर्क पड़ेगा कि घोटाला कितने करोड़ का है, लेकिन इसकी निरंतरता में आई गिरावट का जिक्र जरूर होगा। कुछ इसी तरह आखिरी सालों में आ रही परिवहन निगम की नई बसों से यातायात में क्या अंतर आएगा, इसके बजाय यह कि सदन में मुद्दे ने अपनी आवश्यकता बताई। हिमाचल अपने विकास के मामले में कहीं आवश्यकता से अधिक, तो कहीं निरंतरता में कमजोर रहा है। नए स्कूलों की परिधि में विकास की आवश्यकता को पहचाना ही नहीं गया, नतीजतन स्कूलों को डिनोटिफाई करने का सिलसिला जारी है। बीस मार्च की अधिसूचना के अनुसार राज्य में शून्य छात्र संख्या के 36 सरकारी स्कूल डिनोटिफाई हो गए। कुछ यही हाल कालेज, मेडिकल कालेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने से भी हुआ। सरकार एड़ी चोटी का प्रयास करते हुए मेडिकल कालेजों में सुविधाएं बढ़ा रही है, लेकिन चिकित्सा का मूल आधार डिस्पेंसरी से शुरू होता है।

कुछ अलग

भीतरी अदालत का न्याय संवारेगा जीवन

आए दिन समाज में ऐसी खबरें आती हैं कि धनाढ्य और जीवन में सफल लोगों का व्यक्तिगत जीवन भी अशांत है। वे न केवल शारीरिक रूप से ही अस्वस्थ थे बल्कि मानसिक रूप से भी उतने ही अशांत होते हैं। जीवन में तमाम कामयाबियों व धन-दौलत जुटाने के बाद भी ऐसे लोगों को नींद नहीं आती। हमारी नींद का सीधा रिश्ता हमारे कार्यों की गुणवत्ता और जीवन की सहजता से होता है। मानवीय श्रम भी उसका एक बड़ा कारक है। धारणा बनने लगी है कि आज के गलाकाट स्पर्धा दौर में तुरंत सफलता व संपदा खालिस मेहनत-ईमानदारी से हासिल नहीं होती। एक व्यापारी को अपने मुनाफे के लिए दिन में सौ बार झूठ बोलना पड़ता है। रात को जब वह बिस्तर में सोने जाता है तो दिनभर के खटकर्म उसे सोने नहीं देते। उसके अंतर्मन की अदालत उसके कृत्यों का हिसाब-किताब मांगती है। व्यक्ति चाहकर भी अपनी दौलत, शोहरत और सुख-सुविधाओं का सुख नहीं भोग पाता है। वास्तव में जिसे हम सफलता मानते हैं वह बाहरी दुनिया का बहलावा मात्र है। जरूरी नहीं कि वह हमें सुख और मानसिक शांति भी दे। व्यक्ति जब भी कोई अन्याय या शोषण करता है तो उसका अंतर्मन उसे सचेत करता है। उसे अहसास कराता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मनुष्य की भीतरी चेतना उसे गलत के प्रति सचेत करती है। अच्छा इंसान व संत तो इसे सुनकर अपनी नीति व कार्यशैली का निर्धारण करता है, लेकिन संवेदना खो चुका व्यक्ति इसे नजरअंदाज कर देता है। सही मायनों में हर व्यक्ति के भीतर यह न्याय व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। वैसे तो दुनियावी अदालतें भी न्याय देने का काम करती हैं।

टेलीविजन और वेब सीरीज के माध्यम से पूरी दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वह दक्षिण कोरिया है

कोरियन ड्रामा से भारतीय सीरियल तक : मनोरंजन की दिशा पर पुनर्विचार

ललित गर्ग

विश्व के मनोरंजन जगत में पिछले कुछ वर्षों में यदि किसी देश ने टेलीविजन और वेब सीरीज के माध्यम से पूरी दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वह दक्षिण कोरिया है। कोरियन ड्रामा आज केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक शिक्षा, भावनात्मक परिपक्वता और जीवन मूल्यों के प्रस्तुतीकरण का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। भारत सहित दुनिया के करोड़ों लोग कोरियन ड्रामा देख रहे हैं और उनसे प्रभावित हो रहे हैं। यह केवल तकनीक या अभिनय का प्रभाव नहीं है, बल्कि उनकी कहानियों की संवेदनशीलता, जीवन की वास्तविकता और मानवीय रिश्तों की गहराई का प्रभाव है। कोरियन ड्रामा का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे जीवन की वास्तविक समस्याओं को बहुत संवेदनशील और मानवीय तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनमें परिवार है, प्रेम है, संघर्ष है, बीमारी है, मानसिक तनाव है, करियर की समस्याएं हैं, सामाजिक दबाव है, लेकिन इन सबके साथ समाधान भी है, आशा भी है, सकारात्मकता भी है। वे केवल समस्या नहीं दिखाते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। उनके पात्र अतिनाटकीय या अवास्तविक नहीं होते, बल्कि आम आदमी जैसे होते हैं, जिनकी समस्याएं भी वास्तविक होती हैं और संघर्ष भी वास्तविक होता है। कोरियन ड्रामा की एक विशेषता यह भी है कि वे सीमित एपिसोड में एक पूर्ण कहानी प्रस्तुत करते हैं। उनमें अनावश्यक विस्तार, अंतहीन षड्यंत्र और कृत्रिम मोड़ नहीं होते। कहानी का एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य पूरा होते ही कहानी समाप्त हो जाती है। इस कारण उनमें कसाव, गुणवत्ता और प्रभाव बना रहता है। वे दर्शकों के समय और संवेदना दोनों का सम्मान करते हैं।

कोरियन ड्रामा आज केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक शिक्षा, भावनात्मक परिपक्वता और जीवन मूल्यों के प्रस्तुतीकरण का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। भारत सहित दुनिया के करोड़ों लोग कोरियन ड्रामा देख रहे हैं और उनसे प्रभावित हो रहे हैं। यह केवल तकनीक या अभिनय का प्रभाव नहीं है, बल्कि उनकी कहानियों की संवेदनशीलता, जीवन की वास्तविकता और मानवीय रिश्तों की गहराई का प्रभाव है। कोरियन ड्रामा का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे जीवन की वास्तविक समस्याओं को बहुत संवेदनशील और मानवीय तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनमें परिवार है, प्रेम है, संघर्ष है, बीमारी है, मानसिक तनाव है, करियर की समस्याएं हैं, सामाजिक दबाव है, लेकिन इन सबके साथ समाधान भी है, आशा भी है, सकारात्मकता भी है।

यदि हम भारतीय टीवी सीरियल्स की ओर देखें, तो स्थिति इसके विपरीत दिखाई देती है। अधिकांश धारावाहिक सास-बहू के अंतहीन संघर्ष, पारिवारिक षड्यंत्र, पुनर्जन्म, चमत्कार, बदला, ईर्ष्या और दिखावे के जीवन के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। एक ही कहानी वर्षों तक चलती रहती है और उसमें वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता। परिवार, जो प्रेम,

सहयोग और संवाद का केंद्र होना चाहिए, उसे षड्यंत्र और राजनीति का केंद्र बना दिया जाता है। इससे समाज में नकारात्मक मानसिकता का निर्माण होता है। भारतीय फिल्मों की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है। अधिकांश फिल्में मारधाड़, हीरोगिरी, बदला, अपराध या अवास्तविक प्रेम कहानियों पर आधारित होती हैं। उनमें वास्तविक जीवन की समस्याओं और उनके समाधान पर बहुत कम काम होता है। जबकि आज समाज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, वे अलग हैं-मानसिक तनाव, अवसाद, अकेलापन, पारिवारिक विघटन, पीढ़ियों के बीच संवाद की कमी, बेरोजगारी, करियर का दबाव, स्वास्थ्य समस्याएं, नशा, पर्यावरण संकट आदि। इन विषयों पर आधारित मनोरंजन बहुत कम देखने को मिलता है।

कोरियन ड्रामा की लोकप्रियता का एक कारण यह भी है कि वे दर्शकों को भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। उन्हें देखकर व्यक्ति केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ता है, जीवन को समझता है, रिश्तों की अहमियत को समझता है, धैर्य और संघर्ष की प्रेरणा पाता है। कई कोरियन ड्रामा मानसिक स्वास्थ्य, अवसाद, ऑटिज्म, अस्पताल जीवन, वकीलों के संघर्ष, शिक्षकों के जीवन, छोटे उद्यमियों के संघर्ष जैसे विषयों पर बने हैं। वे दर्शकों को संवेदनशील बनाते हैं, आक्रामक नहीं। भारत में भी कुछ अच्छे धारावाहिक बने हैं, जैसे "हम लोग", "बुनियाद", "संजीवनी", "बालिका वधू", "उड़ान", "तारक मेहता का उल्टा चश्मा" आदि, जिन्होंने समाज को कुछ सकारात्मक संदेश दिए। लेकिन ऐसे धारावाहिकों की संख्या बहुत कम है। आज जरूरत ऐसे धारावाहिकों और फिल्मों की है जो समाज को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएं, जीवन जीने की कला सिखाएं, तनाव से मुक्ति का मार्ग दिखाएं, परिवार को जोड़ने का संदेश दें और सकारात्मक सोच का निर्माण करें।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोरंजन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, बल्कि मन का निर्माण होना चाहिए। यदि फिल्म या धारावाहिक देखकर व्यक्ति अधिक आक्रामक, असंतुष्ट, तनावग्रस्त या अवास्तविक जीवन की कल्पनाओं में खो जाए, तो वह मनोरंजन नहीं, मानसिक प्रदूषण है। लेकिन यदि कोई फिल्म या धारावाहिक व्यक्ति को प्रेरित करे, जीवन में आशा जगाए, समस्याओं से लड़ने की शक्ति दे, रिश्तों को समझने की दृष्टि दे, तो वह वास्तविक मनोरंजन है। आज समाज में मानसिक बीमारियां, अवसाद, अकेलापन और तनाव तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में मनोरंजन उद्योग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उन्हें ऐसे धारावाहिक और फिल्में बनानी चाहिए जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को स्वस्थ बनने की प्रेरणा दें, सकारात्मक सोच का निर्माण करें, योग, ध्यान, संवाद, परिवार, मित्रता और जीवन के उद्देश्य के महत्व को दिखाएं। यदि इस दिशा में काम किया जाए, तो मनोरंजन उद्योग समाज के लिए वरदान बन सकता है।

यह भी विचारणीय है कि आखिर क्यों हमारे अधिकांश सीरियल सास-बहू के संघर्ष से शुरू होकर षड्यंत्र और बदले पर समाप्त होते हैं, और हमारी फिल्में मारधाड़ और हीरोगिरी पर आधारित होती हैं। इसका एक कारण यह है कि निर्माता यह मानते हैं कि दर्शक यही देखना चाहते हैं। लेकिन यह आधा सच है। वास्तविकता यह है कि दर्शकों को अच्छा, संवेदनशील और सार्थक कंटेंट मिलेगा, तो वे उसे भी उतना ही पसंद करेंगे, जैसा आज वे कोरियन ड्रामा को पसंद कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि समस्या दर्शकों की पसंद में नहीं, बल्कि कंटेंट की दिशा में है। समय आ गया है कि भारतीय मनोरंजन जगत अपनी दिशा पर पुनर्विचार करे। उन्हें यह सोचना होगा कि वे समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या वे समाज को संवेदनशील, सकारात्मक और स्वस्थ बना रहे हैं, या केवल मनोरंजन के नाम पर नकारात्मकता, हिंसा और षड्यंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं? मनोरंजन उद्योग केवल उद्योग नहीं है, वह समाज निर्माण का माध्यम भी है।

कोरियन ड्रामा हमें यह सिखाते हैं कि मनोरंजन भी समाज को शिक्षित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, भावनात्मक रूप से परिपक्व बना सकता है और जीवन को समझने की दृष्टि दे सकता है। भारतीय सिनेमा और टेलीविजन यदि इस दिशा में काम करें, तो वे केवल मनोरंजन नहीं करेंगे, बल्कि समाज को बेहतर बनाएंगे। मनोरंजन का सर्वोच्च रूप वही है जो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाए, जो निराशा में आशा दे, जो टूटते परिवारों को जोड़ने की प्रेरणा दे, जो तनावग्रस्त व्यक्ति को शांति दे, जो जीवन की समस्याओं का समाधान सिखाए। जब भारतीय धारावाहिक और फिल्में इस दिशा में बननी शुरू होंगी, तब मनोरंजन वास्तव में समाज निर्माण का माध्यम बन सकेगा। यही समय की आवश्यकता है और यही भविष्य की दिशा भी।

देश दुनीया से

रणनीति में युद्ध समाप्ति कला की अहमियत

आजकल युद्ध खत्म नहीं होते। खिंचते जाते हैं, अपना स्वरूप बदल रहे हैं और खुद को जायज ठहराते हैं। यह रणनीति नहीं है। यह रणनीतिक रूपरेखा की असफलता है। मैंने युद्धों को खत्म होते देखा, और उन्हें खत्म होने से इनकार करते भी। सेना में, हमें युद्ध शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हम आरंभिक व्यूह रचना, जोरदार हमले, शत्रु का घेरा तोड़ने व इच्छाशक्ति कुचलने का अध्ययन करते हैं। युद्ध का विस्तार करना समझते हैं। लेकिन एक अन्य शांत अनुशासन है जो कभी रणनीति को परिभाषित करता था, लेकिन अब धीरे-धीरे धुंधला रहा है। वह है, रुकने की कला। जिन संघर्षों का अंत बढ़िया हुआ, उनकी संरचना सीधी-सादी थी। दुश्मन को पूरी तरह मिटाना नहीं, बल्कि उद्देश्य में स्पष्टता रखना। तब, किसी में इतनी हिम्मत होती थी कि वह फैसला कर सके कि मिशन पूरा हो गया है। इसलिए नहीं कि दुश्मन का खात्मा हो गया, बल्कि इसलिए कि काम पूरा हो गया था। बल का इस्तेमाल हुआ। तयशुदा सीमा तक पहुंचे। फिर आया सबसे मुश्किल आदेश : रुको। घर वापसी करो। आज, वह माद्दा गायब है। कोई फैसला नहीं करता। संघर्ष खिंचते रहते हैं। बिना किसी तय अंत वाला युद्ध कोई अभियान नहीं होता। यह तो जान-माल की हानि के साथ भटकाव है।

भारत का 'गोल्ड स्टैंडर्ड' (सर्वोच्च मानक) : हमें किसी मानक की तलाश करने की जरूरत नहीं है। साल 1971 में, भारत ने आधुनिक इतिहास के सबसे निर्णायक अभियानों में से एक को अंजाम दिया। यह सिर्फ़ जीत नहीं थी। यह उसके बाद बरते गए संयम का उदाहरण था। हम वहां रुके नहीं रहे। हमने अपनी जीत को कब्जे में नहीं बदला। हमें भान था कि 'पूरा हुआ काम' कैसे दिखता है। 1988 में मालदीव में, हमने दखल दिया, व्यवस्था बहाल की और वापसी कर ली। पीछे कुछ बाकी नहीं छोड़ी। कोई अन्य एजेंडा नहीं। प्रभाव अधिकतम, दखल न्यूनतम। यहां तक कि श्रीलंका में भी, जहां पर हालात बहुत पेचीदा थे, हमने तब पीछे हटने का अनुशासन दिखाया, जब हमें लगा कि अब वहां से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। भारत का संयम सिर्फ़ इसमें नहीं था कि उसने क्या किया, बल्कि इस बात में भी था कि उसने किन चीज़ों पर हमला न करना चुना। बुनियादी ढांचे को कभी भी निशाना नहीं बनाया। इसी आधारभूत ढांचे पर किसी भी समाज का जीवन टिका होता है। इसे तबाह करने का मतलब है, उन्हीं लोगों को सज़ा देना जिनके नाम पर अक्सर युद्धों को सही ठहराया जाता है। इसी अनुशासन ने हमारी वैधता को बनाए रखा। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर गौर कीजिए। सटीक। तय परिधि में। उद्देश्यपूर्ण। लक्ष्य हासिल। काम पूरा। और फिर रुक जाना। हरेक मामले में, परिणामों ने साधनों को परिभाषित किया। लेकिन अब साधन खुद मकसद बनने का जोखिम उठा रहे हैं।

सिद्धांत के रूप में भटकाव : हम इसे 'हाइब्रिड वॉर', ग्रे ज़ोन या सोच-समझकर पैदा की गई अस्पष्टता कहते हैं। धरातल पर यह सरल दिखता है। सिद्धांत के आवरण में भटकाव। पश्चिम एशिया में, उद्देश्य बदलते रहते हैं जबकि युद्ध जारी है। कोई दिन निर्णायक जीत मिलने का अहसास

करवाता है। अगले रोज़ लगता है लड़ाई अब लंबी खिंचेगी। बातचीत, विराम और तनाव इस कदर गडमड हो जाते हैं कि शब्दों का अर्थ ही समाप्त हो जाए। यूरोप में, संघर्ष वर्षों तक खिंच गया। उद्देश्यों पर भू-राजनीति की कई परतें चढ़ती गईं व स्पष्टता गायब हो गई। लड़ाई इसलिए जारी नहीं है कि अंतिम लक्ष्य परिभाषित है, बल्कि इसलिए कि कोई इसे परिभाषित नहीं कर रहा। संघर्ष खुद-ब-खुद खिंचता जा रहा है।

आमजन पर असर की हकीकत : रणनीति यह भूल जाती है कि इस भटकाव की कीमत कौन चुकाएगा। रणनीतिकार मैदान ए जंग की बातें करता है। नागरिक इसकी अवधि की कीमत चुकाता है। चाय की दुकान पर बैठा व्यक्ति सिद्धांत नहीं पढ़ा होता। वह तो बाधित हुई आपूर्ति शृंखलाओं से बढ़ती कीमतों का दंश झेलता है, जो कभी स्थिर नहीं होतीं क्योंकि युद्ध अंतहीन हो चले हैं। वे अपने परिवारों को युद्धक्षेत्रों में फंसा हुआ पाता है जहां से निकलने की कोई राह नहीं। वह उस अनिश्चितता के साथ जीता है जो राष्ट्र की सोच में रम जाती है। जब युद्ध का कोई निश्चित समय होता है, तो समाज संगठित होता है और उबरता है। जब नहीं तो होता, तो अर्थव्यवस्था और भावनाएं उसी के अनुरूप आकार लेने लगती हैं। यदि सफलता को परिभाषित न किया जाए, तो वह कभी प्राप्त ही नहीं होती। असफलता तब स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है।

क्षमता का विरोधाभास : संघर्ष समाप्त करने के लिए हमारे पास पहले से कहीं अधिक संसाधन हैं, फिर भी हम उन्हें समाप्त करने में असमर्थ हैं। ड्रोन, साइबर ऑपरेशन और सटीक हमले घोषित युद्ध से इतर दबाव डालने का जरिया बन गए हैं। हम अनिश्चित काल तक न तो शांति और न ही युद्ध की स्थिति बनाए रख सकते हैं। यह एक तरह का जाल है। क्षमता ने निर्णय लेने की शक्ति का स्थान ले लिया है। युद्ध रोकने को जवाबदेही की आवश्यकता पड़ती है। बताने की जरूरत पड़ती है कि क्या पाया और क्या खोया। इसके लिए जिम्मेवारी लेने की जरूरत होती है। किसी नतीजे की घोषणा करने के मुकाबले में यह कह देना आसान है कि परिस्थिति स्वरूप बदल रही है।

बल का मापन : बल प्रयोग स्पष्टता और उद्देश्य के साथ किया जाए। लेकिन इसकी वैधता विवेक पर आधारित है। यदि एक थप्पड़ ही काफी है, तो लाठी क्यों? यदि उद्देश्य सुधारना है, तो एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे वर्ग को दंड क्यों? बुनियादी ढांचा युद्धक्षेत्र नहीं होता। यह समाज की जीवनधारा होता है। इस पर चोट करने से आप युद्ध को आकार नहीं दे रहे, बल्कि भविष्य को सजा दे रहे हैं। बल का प्रत्येक प्रयोग न केवल लक्षितों पर, बल्कि खुद आरंभकर्ता पर भी असर छोड़ता है। अतिरेक स्मृति, धारणा और प्रतिरोध को आकार देता है। तात्कालिक जो भी लाभ होता है वह अक्सर वैधता में खो जाता है। संतुलित प्रतिक्रिया व्यवहार सुधारती है। अंधाधुंध प्रतिक्रिया पीढ़ियों को घाव देता है जो बार-बार लौट आते हैं।

मानवता बतौर वैश्विक संसाधन : कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और युद्धों ने एक सरल सत्य उजागर किया। किसी भी संकट का असर स्थानीय नहीं रह सकता। एक क्षेत्र में हो रहा युद्ध महाद्वीपों भर में भोजन, ईंधन, व्यापार और भरोसे को बाधित कर देता है।

आप का नजरीया

पाप का नगर

भले ही हम चेस्टर हिल नामक परियोजना में मीन मेख निकालते-निकालते राजनीतिक, ब्यूरोक्रेसी और व्यवस्था के गलियारों को कोसते रहें, मगर सच यह भी है कि पहाड़ की छाती पर हर कोई मूंग दल रहा है। ताजातरीन उदाहरण में सोलन के चेस्टर हिल परियोजना का दानव गुल खिला रहा है। एक वकील की शिकायत पर कई प्रशासनिक अधिकारी सिरमुंडे हो गए, तो पूरी परियोजना ने एक साथ कई प्रश्न छील दिए। अब जांच की दूरबीन से शिकार होगा या यह सच कभी सामने आएगा कि नई बस्तियों में कितना 'सामान' बिका है। पिछले कई वर्षों से एक शाश्वत आरोप झूम रहा है। हिमाचल की नई दौलत में पूरा प्रदेश बिक रहा है। भले ही फाटक धारा-118 के रौब से बंद दिखाई दें या उसूलों की गिनती में जानकारियां और जांच बंटती रहे, मगर सत्य यह है कि विकास की हर टहनी उपद्रवग्रस्त है। इसीलिए धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय में कांगड़ा भूकंप के संदर्भ में मंथन हुआ, तो विख्यात भू विज्ञानी एवं पद्मश्री डा. हर्ष गुप्ता को कहना पड़ता है कि शिमला-मकलोडगंज की बहुमंजिला इमारतें कफन ओढ़े खड़ी हैं। परवाणू से शिमला और चेस्टर हिल के नजदीक घातक पैमानों से पैमाइश हो रही है। अब हिमाचल सिस्मिक जोन-5 से आगे कहीं छह की पारिस्थितिकीय भुजाओं में लटका है, तो समस्या के अंतहीन सिलसिले में कई खलनायक पैदा हो चुके हैं। यह जमीन और जिरह के बीच कानून खोजा जा रहा है, जबकि जरूरत और जिंदगी के बीच न्याय होना चाहिए। चेस्टर हिल परियोजना में क्या हुआ, कैसे जमीन बिकी, भूमि का भूगर्भीय अध्ययन क्या कहता है या भ्रष्टाचार किस-किस स्तर पर हुआ, इससे भी अलग एक समाधान यह भी कि हिमाचल में बसने को जगह नहीं तथा जिंदगी को आशियाना चाहिए। ऐसी सौ और परियोजनाएं भी उभर आएं, तो ग्राहकों की कमी नहीं, लेकिन हर अवतार में कोई न कोई कसूरवार रहेगा। अब यह जांच किसके सिर बोलती है या किसके सिर चढ़ती है, लेकिन हमने तब भी सुना था जब सोलन जिला में इसी तरह कई निजी विश्वविद्यालय खुल गए थे और अब फोरलेन के किलोमीटर की औसत में सडक के किनारे पहाड़ पर मॉल चढ़ गए हैं। हमें गिला न भौगोलिक परिस्थिति से और न ही कानून के पहरे हमें रोक पा रहे हैं। हिमाचल में आ रही दौलत के लिए जमीन बिक रही है। ऐसे में पांच दशक पहले आए टीसीपी कानून की धज्जियां कौन उड़ा रहा है। और यह सिर्फ चेस्टर हिल नहीं शिमला, मकलोडगंज, कसौली, डलहौजी या किसी भी शहर में प्रवेश करते देखना कि मंजिलें बेआबरू होकर, जमीन को कोसती हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में टीसीपी एक्ट लागू होना चाहिए तथा इसी की भावना में जमीन की पूलिंग, नई संरचना की मंजूरी और वैज्ञानिक ढंग से आबाद होने की छूट चाहिए। विकास एक तरफा हो रहा है, तो अनुमतियों के ग्रॉफ में सरकारी पापड़ बेलने की प्रथा ने कई चोर गलियां आबाद कर दीं। यही चोर गली चेस्टर हिल्स का मिलन शिमला के तंत्र से करवा रही थी, मगर आज अगर भाजपा के पास कहने को है तो सारे गड़े मुर्दे उसकी सरकारों को भी कोसते हैं। यह काजल की नगरी हो गई, बस मेरी आंख से चोरी हो गई। अगर हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, तो इसका प्रदर्शन भी होगा और मांग-आपूर्ति का यह खेल चंडीगढ़ के आसपास की साठ फीसदी संपत्तियों में हिमाचलियों को खरीददार बना रहा है, तो प्रदेश का हिमुडा क्या करता रहा। आजादी के बाद एक भी टाउनशिप या उपग्रह नगर न बसा पाने की सजा यह कि हर पहाड़ी कट रही है और खड्डु, नदी या कूहलों के किनारे सिकुड़ गए। करीब पंद्रह साल पहले हिमुडा मांग सर्वेक्षण में करीब 75 हजार लोगों ने फीस डिपॉजिट करके इच्छा जताई कि कुछ नगर या बस्तियां बसा कर, उन्हें सुरक्षित व नियमों में सुदृढ़ आवासीय व्यवस्था का विकल्प दिखाया जाए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जाठिया देवी मंदिर परियोजना बार-बार दरक रही। धर्मशाला के चैतड़ू में एक कालोनी तय हुई तो बीच में कांग्रेस-भाजपा हो गई। पुनः धर्मशाला के नरघोटा में नगर विकास परियोजना का पूरा खाका बन गया, तो इसे विराम लगाते हुए पर्यटन गांव की संभावना में तोल दिया। नतीजा यह कि बस किश्तियां छोड़ी जाती हैं हर सुबह, मंजिल पे तूफान को डेरा दिया जाता है।

परवाणू से शिमला और चेस्टर हिल के नजदीक घातक पैमानों से पैमाइश हो रही है। अब हिमाचल सिस्मिक जोन-5 से आगे कहीं छह की पारिस्थितिकीय भुजाओं में लटका है, तो समस्या के अंतहीन सिलसिले में कई खलनायक पैदा हो चुके हैं। यह जमीन और जिरह के बीच कानून खोजा जा रहा है, जबकि जरूरत और जिंदगी के बीच न्याय होना चाहिए। चेस्टर हिल परियोजना में क्या हुआ, कैसे जमीन बिकी, भूमि का भूगर्भीय अध्ययन क्या कहता है या भ्रष्टाचार किस-किस स्तर पर हुआ, इससे भी अलग एक समाधान यह भी कि हिमाचल में बसने को जगह नहीं तथा जिंदगी को आशियाना चाहिए। ऐसी सौ और परियोजनाएं भी उभर आएं, तो ग्राहकों की कमी नहीं, लेकिन हर अवतार में कोई न कोई कसूरवार रहेगा। अब यह जांच किसके सिर बोलती है या किसके सिर चढ़ती है, लेकिन हमने तब भी सुना था जब सोलन जिला में इसी तरह कई निजी विश्वविद्यालय खुल गए थे और अब फोरलेन के किलोमीटर की औसत में सडक के किनारे पहाड़ पर मॉल चढ़ गए हैं। हमें गिला न भौगोलिक परिस्थिति से और न ही कानून के पहरे हमें रोक पा रहे हैं। हिमाचल में आ रही दौलत के लिए जमीन बिक रही है।

दृष्टि कोण

विनिवेश को रोकना एक सही फैसला

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण को लेकर बहस, चाहे वे औद्योगिक हों या सेवा उद्यम, कोई नई बात नहीं है। 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के बाद से, जिसमें तीन मुख्य आयाम शामिल थे : उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, बैंकों के निजीकरण का मुद्दा हमेशा से ही एक बहुत ही विवादास्पद विषय रहा है। यही कारण है कि सभी सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण से दूर रखा है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश दो तरीकों से होता है : रणनीतिक बिक्री और बाजार-आधारित शेयर बिक्री। रणनीतिक बिक्री में अक्सर मूल्यांकन से जुड़ी समस्याएं, बोली लगाने वालों की सीमित संख्या और पारदर्शिता की कमी के आरोप सामने आते हैं। इसके विपरीत, शेयर बाजार के जरिए किया जाने वाला विनिवेश ज्यादा पारदर्शी होता है। इसमें ज्यादा लोगों की भागीदारी होती है और इससे शेयरों का सही मूल्य तय हो पाता है। पिछले 11 वर्षों में, विनिवेश से होने वाली प्राप्ति लगभग 4.5 लाख करोड़ में से ज्यादातर बाजार बिक्री से ही हुई है, और सिर्फ 69000 करोड़ ही रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त हुआ, जो इस तरीके की ज्यादा प्रभावशीलता को दर्शाता है। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि भारत में पब्लिक सेक्टर के बैंकों को निजी संस्थाओं को बेचने का कोई इतिहास नहीं रहा है। फिर भी, अलग-अलग बैंकों के विलय के जरिए बैंकों की कुल संख्या में निश्चित रूप से कमी आई है। असल में, जहां कुछ समय पहले तक 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, वहीं अब उनकी संख्या घटकर सिर्फ 12 रह गई है। इसके अलावा एक और बैंक है, जिसका नाम आइडीबीआई बैंक है। इसमें हालांकि केंद्र सरकार की शेयरहोल्डिंग 51 प्रतिशत से कम है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी इसमें बड़ी शेयरहोल्डिंग है, जिससे सरकार का कुल नियंत्रण लगभग 95 प्रतिशत हो जाता है। विशेष रूप से आईडीबीआई बैंक के मामले में, पिछले कुछ सालों से सरकार रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कदम बढ़ा रही थी, और इस संबंध में पहले प्रस्ताव आमंत्रित किए गए

थे। हाल की रिपोर्टों के अनुसार भारत सरकार ने अब इस बैंक के रणनीतिक विनिवेश को रोक दिया है। इस मुद्दे पर काफी बहस चल रही थी, और शायद यह किसी बैंक के निजीकरण का अपनी तरह का पहला मामला होता, जिसमें भारत सरकार और सरकारी संस्थाओं की शेयरधारिता काफी बड़ी अधिक थी। क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाना चाहिए, एक लंबी बहस है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से महत्वपूर्ण तर्क दिए जाते रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के आलोचकों के, खासकर आइडीबीआई के मामले में, अपने मजबूत तर्क हैं। लेकिन इस बहस में आगे बढने से पहले, हमें आइडीबीआई बैंक के इतिहास पर नजर डालनी होगी, जो कुछ साल पहले यह एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, वहीं अब यह घाटे से उबर चुका है और एक मुनाफा कमाने वाली संस्था बन गया है। शुरुआत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आइडीबीआई) एक विकास बैंक था, जो एलपीजी नीतियों के प्रभाव में, अन्य विकास वित्तीय संस्थानों की तरह आइडीबीआई को भी बाद में एक वाणिज्यिक बैंक में बदल दिया गया। निजीकरण के पक्ष में तर्क : निजीकरण के समर्थक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की भी वकालत करते हैं। उनका पहला तर्क यह है कि आईडीबीआई के निजीकरण से बाजार अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा और पूंजी का कुशल आवंटन होगा। दूसरा, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नौकरशाही की देरी और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करेगा।

लाल निशान मिटाने वालों दुकानदारों पर सख्ती, बुलडोजर चलाकर कोहाड़ापीर में अवैध दुकानें ध्वस्त

बरेली, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के कोहाड़ापीर इलाके में मंगलवार को नगर निगम का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर चला और पेट्रोल पंप के सामने बनी कई अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में अफरातफरी मच गई और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। नगर निगम ने पहले से ही सड़क किनारे बने अवैध निमार्णों को चिह्नित कर उन पर लाल निशान लगाए थे। आरोप है कि कुछ दुकानदारों ने इन निशानों को मिटा दिया था। इसे गंभीर मानते हुए निगम अधिकारियों ने सबसे पहले उन्हीं दुकानों पर कार्रवाई की। दो बुलडोजरों की मदद से कुछ ही देर में कई अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए गए। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सरकारी निशान मिटाना या उनसे छेड़छाड़ करना गंभीर मामला है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने साफ किया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान अब लगातार जारी रहेगा। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के दूसरे चरण के तहत की जा रही है।

योजना के अंतर्गत कोहाड़ापीर से कुदेशिया मार्ग और धर्मकांटा से कोहाड़ापीर तक सड़क चौड़ीकरण होना है। इसके लिए करीब 50 से 55 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। मंगलवार को मजार के पास बनी अवैध दुकानों को हटाकर अभियान की शुरूआत की गई। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध न हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त मौजूदगी में ध्वस्तीकरण शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया गया। नगर निगम के एक्सईएन राजीव कुमार राठी ने बताया कि सड़क चौड़ी होने से ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और जाम की समस्या में काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शहर के अन्य हिस्सों में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा।

उप्र कैबिनेट : योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में मेट्रो विश्वविद्यालय की स्थापना को दी मंजूरी

-उच्च शिक्षा को बढ़ावा, निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय को कैबिनेट की स्वीकृति

-26.1 एकड़ में बनेगा मेट्रो विश्वविद्यालय, युवाओं को मिलेगा आधुनिक व रोजगारपरक शिक्षा का अवसर

लखनऊ, (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस क्रम में ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत मेट्रो विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जो प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त अधिनियम के तहत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनके विनियमन एवं संचालन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रायोजक संस्था सनहिल हेल्थकेयर प्रा. लि., नोएडा द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आवंटित 26.1 एकड़ भूमि पर मेट्रो विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे विधिक प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण के उपरांत स्वीकृति दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित किए जाने तथा प्रायोजक संस्था को संचालन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे तथा युवाओं को आधुनिक एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह पहल राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता संवर्धन और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी बढ़ेंगे।

लखनऊ में विधानभवन के सामने महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास, पुलिस ने बचाया

लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानभवन के सामने मंगलवार को एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। भवन की सुरक्षा में मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने महिला को बचा लिया। इससे पहले भी महिला ने भवन के सामने जान देने की कोशिश की थी। पुलिस पूछताछ में पीड़ित महिला ने बताया कि उसका नाम संध्या सिंह और गाजीपुर इंदिरा नगर के सेक्टर 22 की रहने वाली है। उसका मानकनगर क्षेत्र में 1600 वर्ग गज की जमीन है, जिस पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उसने कई बार पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसकी फरियाद को सुना नहीं गया। पुलिस और जिला प्रशासन की हीलाहवाली की वजह से उसने 27 फरवरी को भी विधानभवन के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था, लेकिन उस समय मौजूद पुलिस अफसरों ने उसके साथ न्याय और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाकर शांत करा लिया था। लेकिन इसके बावजूद अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से उसने दोबारा यह कदम उठाया है। इस मामले में अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है।

जर्जर भवन में कार्यालय शिफ्टिंग पर बवाल, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने किया विरोध

मीरजापुर, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में हलिया विकासखंड में बाल पुष्टाहार कार्यालय को जर्जर भवन में शिफ्ट किए जाने के फैसले पर मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का आक्रोश फूट पड़ा है। कार्यकत्रियों ने इसे अव्यवहारिक और असुरक्षित बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। जानकारी के अनुसार, पूर्व में खाद-बीज गोदाम के रूप में इस्तेमाल हो चुके भटवारी स्थित भवन में आंगनबाड़ी कार्यालय स्थानांतरित किया जा रहा है। कार्यकत्रियों का कहना है जहां कार्यालय शिफ्ट किया जा रहा है वह भवन पूरी तरह जर्जर है और वहां तक पहुंचने के लिए हलिया बाजार से करीब दो किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। वहां कोई साधन भी उपलब्ध नहीं है, जिससे बैठक और पोषाहार से जुड़े कार्यों में दिक्कत होगी। उन्होंने आशंका जताई ब्लॉक परिसर में चकबंदी न्यायालय संचालित होने से पुरुषों की अधिक आवाजाही रहती है, जो सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। ऐसे में कार्य करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कार्यालय को पूर्व स्थान पर ही संचालित किया जाए। सीडीपीओ दिलीप वर्मा ने बताया उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्यालय को ब्लॉक परिसर में शिफ्ट किया जा रहा है।

कानपुर में आपदा के बाद राहत कार्य हुआ तेज, हर पीड़ित तक मदद पहुंचाने में जुटे विधायक मैथानी

कानपुर, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में बीते दिनों बदले मौसम के चलते आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत कार्यों में तेजी लाते हुए प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं गिरे पेड़ों को हटाकर मार्गों को सुचारू किया जा रहा है और बिजली व्यवस्था बहाल करने के प्रयास लगातार जारी हैं। प्रशासनिक टीमें दिन-रात काम कर रही हैं ताकि जनजीवन जल्द सामान्य हो सके। इसी क्रम में गोविंद नगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र मैथानी जुटे हुए है। उन्होंने मंगलवार को अपने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मेरा लक्ष्य है कि हर प्रभावित परिवार को राहत मिले और क्षेत्र की स्थिति शीघ्र सामान्य हो। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में आए तेज अंधड़ और प्राकृतिक आपदा के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर पुराने और भारी पेड़ गिरने से सड़कें बाधित हो गईं, बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए और स्थानीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। वहीं, कई गरीब परिवारों के कच्चे मकान भी ढह गए, जिससे उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वयं राहत कार्यों की कमान संभाली और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने जिलाधिकारी से वार्डवार सर्वे कराकर प्रभावित परिवारों की सूची तैयार करने और उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एसडीएम सदर को निर्देशित किया गया कि सभी लेखपालों को तत्काल क्षेत्र में भेजकर मकानों के नुकसान का निरीक्षण कराया जाए और रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए। विधायक ने स्पष्ट कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वह शासन स्तर तक मामला उठाकर प्रभावितों को राहत दिलाने में हर संभव सहयोग करेंगे। नगर निगम, वन विभाग और विद्युत विभाग को युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। गिरे पेड़ों को काटकर हटाने, सड़कों को साफ करने और बिजली आपूर्ति बहाल करने का कार्य तेजी से चल रहा है ताकि आमजन को राहत मिल सके। विधायक ने जनता से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए आश्वस्त किया कि प्रशासन पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है और जल्द ही हालात सामान्य कर दिए जाएंगे।

मनरेगा तकनीकी सहायक नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप, अभ्यर्थियों ने की उपायुक्त से जांच की मांग

पूर्वी सिंहभूम, (हि.स.)। पूर्वी सिंहभूम जिले में मनरेगा के तहत तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता समकक्ष) पदों पर हुई संविदा आधारित नियुक्ति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक को आवेदन सौंपकर पूरे मामले की जांच कराने तथा योग्यता के आधार पर नई मेधा सूची प्रकाशित करने की मांग की है। यह मामला विज्ञापन संख्या 01/2023-24 से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कंप्यूटर योग्यता जैसे पीजीडीसीए या कंप्यूटर डिप्लोमा को मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य बताया गया था, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों में कुछ के प्रमाणपत्र इस मानक के अनुरूप नहीं हैं। आवेदनकर्ताओं के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों के पीजीडीसीए प्रमाणपत्र उनके स्नातक की डिग्री से पहले के वर्ष के हैं, जबकि सामान्य रूप से यह पाठ्यक्रम स्नातक के बाद किया जाता है। इस प्रकार के मामलों से चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया है कि निर्धारित पदों की संख्या के बावजूद सभी पदों पर नियुक्ति नहीं की गई। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में चयन को लेकर भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ा है। कुछ विशेष मामलों का उल्लेख करते हुए अभ्यर्थियों ने आवेदन संख्या 623228338149 से संबंधित अभ्यर्थी के शैक्षणिक विवरण पर सवाल उठाया है, जिसमें डिप्लोमा (सिविल) वर्ष 2013, बीटेक (सिविल) वर्ष 2017 और पीजीडीसीए वर्ष 2015 दर्शाया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह शैक्षणिक क्रम संदिग्ध प्रतीत होता है और इसकी गहन जांच आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, शिकायत में यह भी सामने आया है कि कुछ चयनित अभ्यर्थी पहले से ही अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत थे और लाभ प्राप्त कर रहे थे, इसके बावजूद उन्होंने शपथ पत्र में इस तथ्य को छिपाकर आवेदन किया। यह शपथ पत्र की शर्तों का उल्लंघन माना जा रहा है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि गलत जानकारी पाए जाने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त की जा सकती है और विधिक कार्रवाई भी संभव है। शिकायत में जिन अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं, उनमें शीतल महापात्र, अनुपम साहू और अभिजीत बेरा शामिल हैं। इनके आवेदन विवरण और कार्यस्थल से जुड़े तथ्यों की भी जांच की मांग की गई है। आवेदनकर्ता प्रियंका डबलिन और सिद्धार्थ ग्लुश ने उपायुक्त से निष्पक्ष जांच कराते हुए केवल योग्य अभ्यर्थियों को ही नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई, तो योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा।

शहीद की पत्नी को आवास निर्माण के लिए भूमि बंदोबस्ती की स्वीकृति

पश्चिमी सिंहभूम, (हि.स.)। देश की रक्षा करते हुए श्रीनगर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए जवान सेलाय कुदादा के परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए झारखंड सरकार ने उनकी पत्नी बुधनी कुदादा को आवास निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने की स्वीकृति दी है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से पूर्व में जारी संकल्प के तहत यह कार्रवाई की गई है। मंगलवार को जिला उपायुक्त चंदन कुमार ने खूंटपानी अंचल के मौजा अंकोलकुटी स्थित गैरमजरूआ खास भूमि को आवास निर्माण के लिए बंदोबस्त करने की अनुमति प्रदान की। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, थाना संख्या-37 के अंतर्गत खाता संख्या-01, प्लॉट संख्या-351 की कुल 12.5 डिसमील भूमि शहीद की पत्नी बुधनी कुदादा के नाम स्वीकृत की गई है। इस जमीन पर अब वे अपना घर बना सकेंगी, जिससे उनके परिवार को स्थायी आवास की सुविधा मिल सकेगी। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम न केवल शहीद परिवार को आर्थिक सहारा देगा, बल्कि समाज में उनके सम्मान को भी और सुदृढ़ करेगा। लोगों का मानना है कि इस तरह की पहल अन्य परिवारों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी और शहीदों के प्रति समाज में सम्मान की भावना को और मजबूत करेगी।

लोको पायलटों को अग्नि सुरक्षा का दिया गया विशेष प्रशिक्षण

पूर्वी सिंहभूम, (हि.स.)। रेल सिविल डिफेंस की ओर से मंगलवार को इलेक्ट्रिक लोको पायलट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षणार्थी लोको पायलटों को आग लगने की स्थिति में त्वचा जलने के प्रकार, उसकी पहचान, प्राथमिक उपचार और मुआवजा मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए रेल सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने लोको पायलटों को अपने कर्तव्यों के प्रति राष्ट्रीय भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया और आपदा की स्थिति में तत्परता से सेवा देने की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने आग से झुलसने की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि फर्स्ट डिग्री बर्न में त्वचा की ऊपरी परत लाल हो जाती है, सेकंड डिग्री में त्वचा की ऊपरी व निचली परत प्रभावित होती है और फफोले के साथ तेज दर्द होता है। थर्ड डिग्री बर्न में त्वचा की सभी परतें नष्ट हो जाती हैं और नसों तक असर पहुंचता है, जबकि चौथी डिग्री बर्न में जलन हड्डियों तक पहुंच जाती है, जो अत्यंत गंभीर स्थिति मानी जाती है। प्राथमिक उपचार के संबंध में बताया गया कि फर्स्ट डिग्री बर्न की स्थिति में प्रभावित हिस्से को 10 से 15 मिनट तक ठंडे पानी में रखना चाहिए। सेकंड डिग्री में छोटे छालों पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाकर साफ पट्टी बांधनी चाहिए, जबकि थर्ड और चौथी डिग्री बर्न होने पर संक्रमण का खतरा अधिक होता है, इसलिए ऐसे मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाना आवश्यक है। दूसरे सत्र में डेमोंस्ट्रेटर शंकर कुमार प्रसाद ने अग्निशमन उपकरणों के उपयोग, उनके संचालन के नियमों और सावधानियों की जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक लोको पायलट ट्रेनिंग सेंटर के अनुदेशकगण के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर, खड़गपुर, रांची और आद्रा मंडल से आए करीब दो सौ लोको पायलटों ने भाग लिया।

बिहार के 141 रेलवे समपारों पर आरओबी निर्माण की मांग, मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल
मंत्री
उद्योग एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार

Dr. Dilip Kumar Jaiswal
Minister
Dept. of Industries & Road Construction, Bihar

आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी,

विषय: बिहार राज्य अंतर्गत रेलवे के अवशेष 141 समपारों पर सड़क ऊपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने के संबंध में।

[illegible]

सादर,

भवदीय

(डॉ० दिलीप कु० जायसवाल)

श्री अश्विनी वैष्णव,
माननीय रेल मंत्री,
कमरा संख्या– 341, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली–110001

किशनगंज, (हि.स.) बिहार उद्योग एवं पथ निर्माण विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार में शेष 141 रेलवे समपारों पर सड़क ऊपरी पुल (आरओबी) निर्माण की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर देने को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजा है। मंत्री डॉ. जायसवाल ने पत्र में कहा है कि बिहार में सड़कों पर लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव के कारण रेलवे समपारों पर जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। इससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। पत्र में बताया गया कि रेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर बिहार में कुल 219 रेलवे समपारों पर सड़क ऊपरी पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रेलवे बोर्ड द्वारा इनमें से 78 आरओबी के निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसके लिए मंत्री ने रेल मंत्रालय के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। मंत्री ने कहा कि राज्य में शेष बचे 141 समपारों पर यातायात का अत्यधिक दबाव है और बार-बार जाम लगने से आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन स्थानों पर आरओबी निर्माण होने से यातायात सुगम होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और ट्रेनों का आवागमन भी अधिक सुरक्षित हो सकेगा। डॉ. जायसवाल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष 141 रेलवे समपारों पर आरओबी निर्माण की स्वीकृति रेलवे जोनवार प्राथमिकता सूची के आधार पर शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम आयोजित

भागलपुर, (हि.स.)। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मंगलवार को आनन्दराम ढांढनियाँ सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में एक विशेष स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के प्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा विद्यालय के भैया-बहनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमंत कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता महादेव एवं उपस्थित चिकित्सकों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात सभी चिकित्सकों को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने चिकित्सकों से अपने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श लिया और उनके समाधान के उपायों को समझा। इस अवसर पर डॉ. धनंजय चौधरी के निर्देशन में बालिकाओं का टीकाकरण भी किया गया। महिला चिकित्सक डॉ. रोमा यादव ने छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं डॉ. विकास पांडेय ने नेत्र संबंधी समस्याओं के निवारण के उपाय बताए तथा डॉ. सुमन ने आंख, नाक एवं कान से संबंधित रोगों एवं उनके उपचार पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डॉ. ऋषु, डॉ. अभिषेक रंजन, डॉ. मणि शंकर, डॉ. नवनीत, डॉ. प्रिया, डॉ. पलक लोहानी, डॉ. हर्ष गोयल, डॉ. अनामिका कारण, डॉ. अमित रंजन, डॉ. सुष्मिता कुमारी, डॉ. धीरज कुमार, स्टाफ नर्स श्रीमती साक्षी भारती सहित अनेक चिकित्सकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर बिहार सरकार की मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के अंतर्गत निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण का द्वितीय डोज भी दिया गया।

सदर अस्पताल में सख्ती: चोरी पर कार्रवाई, निर्माण एजेंसी को डीएम की कड़ी चेतावनी

सीवान, (हि.स.)। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक मंगलवार को सदर अस्पताल में आयोजित की गई, जिसमें सदर अस्पताल समेत जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीएम ने सदर अस्पताल में एसी पाइप चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए. डीएम ने कहा कि इस तरह की घटनाएं चिंताजनक हैं और अस्पताल जैसे संवेदनशील संस्थान में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस द्वारा मामले में चल रहे अनुसंधान की जानकारी लेते हुए परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को और प्रभावी बनाने तथा आवश्यक स्थानों पर नए कैमरे लगाने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। बैठक में बताया गया कि चोरी की घटना के कारण मरीजों को असुविधा हुई है, जिसे शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों की सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी न हो। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिले में लगातार डॉक्टरों की बहाली की जा रही है। जानकारी दी गई कि हाल की बैठकों के बाद 30 से अधिक नए डॉक्टरों ने जिले में योगदान दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी। इसके अलावा अस्पताल परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई. पुराने ब्लॉक को तोड़कर नए 50 बेड वाले सीसीयू भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है. साथ ही 100 बेड के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का निर्माण भी तेजी से चल रहा है, जिसे अगले 2-3 महीनों में जनता की सेवा के लिए समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कर रही एजेंसी को सख्त निर्देश दिया कि कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से ग्रीन सेफ्टी नेट लगाकर ही काम किया जाए. साथ ही पुराने भवनों को तोड़ने से पूर्व पानी का नियमित छिड़काव कराने को कहा, ताकि धूल से मरीजों और परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित एजेंसी पर आर्थिक दंड लगाने की चेतावनी भी दी गई। डीएम ने सिविल सर्जन के साथ अस्पताल परिसर का निरीक्षण भी किया और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मासिक रैंकिंग में जिले की स्थिति में सुधार पर सिविल सर्जन एवं पूरी टीम को बधाई दी. हालांकि, डीएम ने ओपीडी में वेटिंग टाइम और मरीजों के यात्रा समय को कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी एमओआईसी और संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार ही प्रशासन की प्राथमिकता है।

होर्मुज संकट से तेल में उछाल, क्रूड 110 डालर के पार

डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.26 डालर की तेजी के साथ 113.67 डालर प्रति बैरल

नई दिल्ली

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच टकराव के चलते वैश्विक कच्चे तेल बाजार में उबाल आ गया है। स्ट्रेट आफ होर्मुज को लेकर जारी विवाद के बीच तेल की कीमतों में मंगलवार को तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसने स्ट्रेट आफ होर्मुज को जल्द नहीं खोला, तो अमेरिका सख्त कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर ईरान को पूरी तरह निशाना बनाया जा सकता है। इस बयान के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड करीब 0.5 फीसदी बढ़कर 110.34 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.26 डालर की तेजी के साथ 113.67 डालर प्रति बैरल पर कारोबार करता नजर आया। दरअसल, स्ट्रेट आफ होर्मुज दुनिया के कुल तेल सप्लाई का करीब 20 फीसदी हिस्सा संभालता है। 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के हमलों के बाद ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था, जिसके चलते जहाजों की आवाजाही सीमित हो गई है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से आए अमेरिकी प्रस्ताव को भी ईरान ने खारिज कर दिया है और स्थायी समाधान की मांग की है।

मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में फिर नंबर-1 बनी हयूदै क्रेटा

नई दिल्ली। भारतीय आटो बाजार में हयूदै क्रेटा ने पुनः अपना दबदबा कायम रखा है। बीते महिने मार्च 2026 में क्रेटा इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बनी, जिसे कुल 17,838 ग्राहकों ने खरीदा। यह कार देश की ओवरआल बिक्री में भी तीसरे स्थान पर रही, जहां इससे आगे सिर्फ टाटा पंच और टाटा नेक्सान ही रहे। क्रेटा को ग्राहकों के बीच खास बनाते हैं इसके एडवांस फीचर्स और प्रीमियम कैबिन। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वाइस-कंट्रोल्ड पैनोरमिक सनरूफ जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो ड्राइविंग अनुभव को और बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा, एसयूवी में कई स्मार्ट कनेक्टेड टेक्नोलाजी फीचर्स भी शामिल हैं। डिजाइन की बात करें तो क्रेटा का लुक काफी बोल्ड और आकर्षक है। इसमें बड़ी पैरामेट्रिक ग्रिल, क्वाड-एलईडी हेडलैम्प्स और होराइजन एलईडी डीआरएल इसे एक प्रीमियम अपील देते हैं। साइड प्रोफाइल में मस्कुलर लाइन्स, अलाय व्हील्स और फ्लोटिंग रूफ डिजाइन इसे स्पोर्टी अंदाज देते हैं। सेफ्टी के मामले में भी क्रेटा मजबूत है। पावरट्रेन के तौर पर इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.72 लाख रुपये से शुरू होकर 20.20 लाख रुपये तक जाती है, जो इसे इस सेगमेंट में एक मजबूत और लोकप्रिय विकल्प बनाती है।

न्यूज ब्रीफ

एयर इंडिया में बड़ा बदलाव, सीईओ कैंपबेल विल्सन ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन में बड़े नेतृत्व बदलाव की खबर सामने आई है। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि नए प्रमुख की नियुक्ति तक वह जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। एयर इंडिया में एक अहम बदलाव के तहत सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका इस्तीफा कंपनी के बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि, नेतृत्व में किसी प्रकार की अस्थिरता से बचने के लिए विल्सन सितबर 2026 तक या नए सीईओ की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे। बताया जा रहा है कि विल्सन पहले ही संकेत दे चुके थे कि वे लंबे समय तक इस पद पर नहीं रहेंगे। इसी कारण कंपनी ने जनवरी 2026 से ही नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी थी। इस पद के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई अनुभवी एविएशन लीडर्स के नामों पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। कैंपबेल विल्सन का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब एयर इंडिया कई चुनौतियों से जूझ रही है। एयरलाइन को परिचालन बाधाओं, बढ़ती ईंधन लागत और वैश्विक हालात के चलते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का घाटा 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

ग्रामीण और खराब रास्तों पर आरामदायक सफर का अनुभव देती है ये एसयूवी

नई दिल्ली। गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के साथ गांव और हिल स्टेशन के सफर के लिए मजबूत और भरोसेमंद एसयूवी के कई विकल्प बाजार में मौजूद हैं। इनमें से एक मजबूत विकल्प है महिंद्रा थार रावस, जो आफ-रोड क्षमता और परिवार के लिए पर्याप्त स्पेस के साथ आता है। वहीं मारुति सुजुकी जिम्नी हल्के वजन और 4गुणा4 सिस्टम के कारण संकरे और कीचड़ भरे रास्तों पर बेहतरीन प्रदर्शन करती है। इसके अलावा महिंद्रा स्कार्पियो-एन अपनी लैडर-आन-फ्रेम चेसिस और दमदार इंजन के कारण ग्रामीण और खराब रास्तों पर आरामदायक और सुरक्षित अनुभव देती है। अगर रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण हो तो फोर्स गुरखा बड़े टायर और मजबूत बाडी के साथ कठिन आफ-रोड परिस्थितियों में भी आसानी से निकल जाती है। लंबी दूरी और भरोसे के लिहाज से टोयोटा फार्च्यूनर को भी एक मजबूत विकल्प माना जाता है, जो मजबूती, आराम और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। इन सभी वाहनों में से किसी एक का चुनाव आपके सफर को न सिर्फ आरामदायक बना सकता है बल्कि खराब रास्तों पर भी बिना परेशानी के आगे बढ़ने में मदद करता है। मालूम हो कि गर्मियों की छुट्टिया शुरू होते ही लोग अपने गांव या किसी शांत हिल स्टेशन की ओर रुख करते हैं। हाईवे खत्म होने के बाद जैसे ही कच्ची, धूल भरी और पथरीली सड़कों का सफर शुरू होता है, गाड़ी की असली परीक्षा भी वहीं से शुरू हो जाती है। तेज धूप में एयर कंडीशनर का ठीक से काम न करना या खराब रास्तों पर सस्पेंशन का साथ छोड़ देना पूरे सफर का मजा खराब कर सकता है।

बिक्री और लोकप्रियता में सभी को पीछे छोडा मारुति अर्टिगा ने

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी की 7-सीटर एमपीवी मारुति अर्टिगा ने बिक्री और लोकप्रियता में सभी को

पीछे छोड दिया है। बीते मार्च महीने में इस कार की 17,072 यूनिट्स की बिक्री हुई, जिससे यह देश की टाप-10 कारों की सूची में पांचवें स्थान पर रही। खास बात यह है कि अर्टिगा ने अपनी ही कंपनी की लोकप्रिय कारों जैसे वैगनआर, बलेनो और फ्रोंक्स को पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, इसने अपने सेगमेंट की मजबूत प्रतिद्वंद्वी महिंद्रा स्कार्पियो को भी पछाड़ दिया, जिसकी इसी अवधि में 14,578 यूनिट्स बिकीं। टाप-10 सूची में अर्टिगा और स्कार्पियो ही दो 7-सीटर कारें रहीं। अर्टिगा की सफलता का अंदाजा इसके कुल बिक्री आंकड़ों से लगाया जा सकता है। लान्च के बाद से अब तक यह कार 14 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिससे यह एमपीवी सेगमेंट में सबसे भरोसेमंद विकल्प बन गई है। शुरुआत में सीमित बिक्री से सफर शुरू करने वाली यह कार अब हर साल लाखों ग्राहकों की पहली पसंद बन रही है। वित्त वर्ष 2026 के फरवरी तक ही इसकी 1,81,783 यूनिट्स बिक चुकी हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि यह साल कंपनी के लिए रिकार्डतोड़ साबित हो सकता है।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। हालांकि डाउ जान्स फ्यूचर्स गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में छुट्टी होने की वजह से पिछले सत्र के दौरान कोई कारोबार नहीं हुआ। वहीं एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है।

पश्चिम एशिया में जारी जंग को रोकने के लिए सोमवार को आए दो शांति प्रस्तावों की वजह से अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान उत्साह का माहौल बना रहा। इस उत्साह के कारण वाल स्ट्रीट के सूचकांक बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे। डाउ जान्स इंडस्ट्रियल एवरेज 165.21 अंक यानी 0.36 प्रतिशत की मजबूती के साथ 46,669.88 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.44 प्रतिशत की तेजी के साथ 6,611.83 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 117.16 अंक यानी 0.54 प्रतिशत उछल कर 21,996.34 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर, ईरान द्वारा युद्ध रोकने के दोनों प्रस्तावों को खारिज कर दिए जाने की वजह से डाउ जान्स फ्यूचर्स 0.15 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 46,601.01 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से पांच के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि तीन सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। हांगकांग स्टाक एक्सचेंज में छुट्टी होने की वजह से हैंग सेंग इंडेक्स में कोई उतार-चढ़ाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।

गिफ्ट निफ्टी 152.50 अंक यानी 0.66 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,848.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,958.44 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा निक्केई इंडेक्स 64.68 अंक यानी 0.12 प्रतिशत फिसल कर 53,349 अंक के स्तर तक गिर गया है।

दूसरी ओर, कोस्पी इंडेक्स 0.22 प्रतिशत की मजबूती के साथ 5,462.05 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.28 प्रतिशत उछल कर 1,458 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। ताइवान वेटेड इंडेक्स में अच्छी तेजी नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 485.02 अंक यानी 1.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 33,057.45 अंक के स्तर तक आ गया है। इसके अलावा जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.42 प्रतिशत की छलांग लगा कर 7,019.08 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.03 प्रतिशत की मामूली मजबूती के साथ 3,881.17 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

मारुति सुजुकी की पापुलर सेडान मारुति डिजायर का दबदबा

नई दिल्ली। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की पापुलर सेडान मारुति डिजायर ने पुनः अपना दबदबा साबित किया है। बीते महीने मार्च में यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, जहां इसकी 21,224 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई। इसके अलावा हयूदै क्रेटा, मारुति ईर्टिगा और मारुति वैगनआर जैसी कारें भी सूची में शामिल रहीं, लेकिन डिजायर की बिक्री के आंकड़े को कोई पार नहीं कर सका। इस दौरान इसने टाटा पंच और टाटा नेक्सान जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को भी पीछे छोड़ दिया। मार्च की टाप-10 कारों की सूची में डिजायर पहले स्थान पर रही, जबकि पंच और नेक्सान क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में भी डिजायर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2,07,906 यूनिट्स की बिक्री के साथ नंबर-1 का ताज अपने नाम किया। यह उपलब्धि खास इसलिए भी है क्योंकि एसयूवी सेगमेंट की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद डिजायर ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी है। साथ ही इसमें 9-इंच टचस्क्रीन, क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो इसे ग्राहकों के लिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प बनाते हैं। फीचर्स की बात करें तो डिजायर में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो बेहतर माइलेज और स्मूथ परफार्मेंस देता है। इसके सीएनजी वेरिएंट का माइलेज 33 किमी/किग्रा तक बताया जाता है।

एलपीजी -पीएनजी टैक्स फ्री करने की मांग तेज

नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय तनाव के चलते गैस सप्लाई पर असर पड़ने के बाद देश में एलपीजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। इस बीच व्यापारिक संगठन ने सरकार से इन पर लगने वाले टैक्स हटाने की मांग की है, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। अमेरिका और इरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में गैस कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी सप्लाई प्रभावित होने के कारण हाल ही में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं।

इसी बीच चेंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज (सीटीआई) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एलपीजी और पीएनजी को टैक्स-फ्री करने की मांग की है। सीटीआई का कहना है कि टैक्स हटाने से गैस की कीमतों में सीधी कमी आएगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर पर 18 फीसदी एसटी वसूला जाता है। दूसरी ओर, पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) जीएसटी के दायरे से बाहर है और इस पर राज्य सरकारें 3 से 14.5 फीसदी तक वैट वसूलती हैं। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में पीएनजी पर 5 फीसदी वैट लागू है। अगर सरकार एनजीजी पर से जीएसटी हटा देती है, तो इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। दिल्ली में वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपये है, जो 5 फीसदी जीएसटी हटने पर करीब 43 रुपये सस्ती होकर लगभग 869 रुपये रह जाएगी। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2078.50 रुपये से घटकर करीब 1761 रुपये हो सकती है, यानी लगभग 317 रुपये की राहत।

व्यापारिक संगठन ने केंद्र सरकार से टैक्स हटाने की अपील की

टीवीएस मोटर के लिए वित्त वर्ष 2025-26 रहा बेहद शानदार

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2025-26 टीवीएस मोटर कंपनी के लिए बेहद शानदार रहा है। अपने इतिहास में पहली बार कंपनी ने 59 लाख वाहनों की बिक्री का आंकड़ा पार किया है। यह आंकडा पिछले साल के मुकाबले 24 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी को दर्शाता है। इस उपलब्धि के पीछे घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिली मजबूत मांग का बड़ा योगदान रहा है। मार्च 2026 में भी कंपनी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए कुल 5,19,358 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो सालाना आधार पर 25 प्रतिशत अधिक है। मार्च महीने में टू-व्हीलर सेगमेंट में कंपनी का दबदबा साफ दिखाई दिया। इस दौरान टीवीएस ने 4,98,134 दोपहिया वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। घरेलू बाजार में मोटरसाइकिल की बिक्री 18 प्रतिशत बढ़ी, जबकि स्कूटर सेगमेंट ने 31 प्रतिशत की तेज वृद्धि के साथ 2,17,624 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिससे यह सेगमेंट कंपनी की ग्रोथ का प्रमुख आधार बना। इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में भी टीवीएस ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। कंपनी के लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस आईक्यूब और टीवीएस आर्बिटर की वजह से ईवी बिक्री में 44 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई। मार्च में कंपनी ने 38,877 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की, जिससे यह जीरो-इमिशन सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा, थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी 46 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 21,224 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई।

सर्राफा बाजार में सस्ता हुआ सोना, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में गिरावट का रुख नजर आ रहा है। दूसरी ओर चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोने की कीमत में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,50,650 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,38,090 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,38,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। वहीं चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु भी दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार के भाव यानी 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ही बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,50,800 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,240 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,50,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,38,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,50,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,140 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,50,650 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,38,090 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,50,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,38,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,38,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,38,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,38,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,38,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

केंद्र सरकार उद्योगों को देगी राहत, स्पेशल क्रेडिट गारंटी स्कीम का ड्राफ्ट तैयार

नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी जंग के कारण दुनिया के तमाम देशों की तरह ही भारत की अर्थव्यवस्था पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस दबाव की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ ही सप्लाई और सर्विस सेक्टर पर भी काफी नकारात्मक असर पड़ा है। संकट की स्थिति में केंद्र सरकार जल्दी ही बड़ा राहत पैकेज जारी करने का ऐलान कर सकती है।

स्पेशल क्रेडिट गारंटी स्कीम नाम के ढाई लाख करोड़ के इस राहत पैकेज का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही इस ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस राहत पैकेज को कोरोना संकट के दौरान साल 2020 में लाई गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीजीएलएस) के तर्ज पर तैयार किया गया है। हालांकि इस राहत पैकेज का दायरा और बजट ईसीजीएलएस की तुलना में काफी अधिक बड़ा होगा। जानकारों के अनुसार इस क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए केंद्र सरकार उन सभी सेक्टर्स को वित्तीय सहायता देगी, जो पश्चिम एशिया में जारी जंग की वजह से प्रभावित हुए हैं। खासकर, जिन सेक्टर्स को युद्ध के कारण सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इस राहत पैकेट के जरिए वित्तीय सहायता देकर लिक्विडिटी क्रंच से बचाने की कोशिश की जाएगी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार राहत पैकेज के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) के जरिए कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज पर केंद्र सरकार 90 प्रतिशत की क्रेडिट गारंटी देगी। क्रेडिट गारंटी का मतलब है कि अगर कर्ज लेने वाली कोई कंपनी किस्तों का भुगतान करने में विफल रहती है, तो बैंक को होने वाले नुकसान के 90 प्रतिशत हिस्से की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। सरकार की इस गारंटी के कारण बैंक बिना किसी डर के जरूरतमंद कंपनियों को कर्ज दे सकेंगे। कोरोना काल में शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की तरह ही इस राहत पैकेज में भी कर्ज लेने वाली कंपनियां को कोई अतिरिक्त सुरक्षा या अतिरिक्त गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी। इस योजना के लिए चार साल की अवधि का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार कर्ज लेने वाली कंपनियों को मूलधन चुकाने के लिए अधिकतम एक साल की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। हालांकि इस अवधि में कंपनियों को नियमित तौर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। 2020 में शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीजीएलएस) के तहत छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई (माइक्रो, स्मालर एंड मीडियम इंटरप्राइजेज) सेक्टर की कंपनियों को मदद दी गई थी, लेकिन सरकार का इरादा इस बार इस राहत पैकेज को सिर्फ एमएसएमई तक ही सीमित रखने का नहीं है। इस बार लघु उद्योगों के साथ ही पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित हर सेक्टर को राहत पहुंचाया जाएगा। हालांकि इस योजना में राहत पैकेज का एक बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर के लिए रिजर्व रहेगा, ताकि उन्हें लिक्विडिटी क्रंच की स्थिति से बचाया जा सके। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण रा मटेरियल की कमी का सामना कर रही कंपनियां और अपने माल का आयात तथा निर्यात करने में परेशानियों का सामना करने वाली कंपनियों को भी इस राहत पैकेज के जरिये मदद पहुंचाई जाएगी।

भारतीय अंडर-17 महिला फुटबाल टीम रूस में खेलेगी 3मैत्री मैच

नई दिल्ली

भारत की अंडर-17 महिला फुटबाल टीम रूस के सोची में 11, 14 और 17 अप्रैल 2026 को मेजबान टीम के खिलाफ तीन मैत्री मैच खेलेगी। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने इस दौरे के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा की है।

सभी मुकाबले सोची के मात्सेस्टा फुटबाल सेंटर में खेले जाएंगे यंग टाइग्रेसेस, जो एएफसी अंडर-17 महिला एशियन कप चीन 2026 की तैयारियों में जुटी हैं, 6 अप्रैल की रात सोची पहुंची। पिछले महीने टीम ने यांगून का दौरा किया था, जहां उसने मेजबान टीम के खिलाफ दो मैत्री मैच खेले और दोनों में जीत दर्ज की (2-0 और 3-2)। इसके बाद टीम ने बेंगलुरु में अपना प्रशिक्षण शिविर जारी रखा। एशियन कप में, जो सुझोउ में खेला जाएगा, भारत को ग्रुप बी में आस्ट्रेलिया (2 मई), जापान (5 मई) और लेबनान (8 मई) के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं।

रूस दौरे के लिए भारत अंडर-17 महिला टीम (23 सदस्यीय):

गोलकीपर: मुन्नी, सूरजमुनी कुमारी, तम्फसाना देवी कोंजेंगबम

डिफेंडर: एलेना देवी सारंगथेम, अलीशा लिंगदोह, दिव्यानी लिंडा, एलिजाबेथ लकड़ा, जायशिनी चानू हुइद्रोम, रितु बड़ाइक, तानिया देवी तोनंबम

मिडफील्डर: अभिस्ता बसनेट, अल्वा देवी सेंजम, बोनिफिलिया शुल्लई, जूलन नोंगमैथेम, प्रीतिका बर्मन, रेडिमा देवी चिंगखामायुम, थंदामोनी बास्के

फारवर्ड: अनुश्का कुमारी, अन्विता रघुरामन, जाय, ओलिविया चानू निंगथौजाम, पर्ल फर्नांडिस, वलैना फर्नांडिस

कोचिंग स्टाफ:

मुख्य कोच: पामेला कोंटी

सहायक कोच: विन्सेन्जो कोंटी, निवेथा रामदास

गोलकीपिंग कोच: मारियो अगियार

स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच: अमित यादव

मैच कार्यक्रम:

- 11 अप्रैल: रूस बनाम भारत (दोपहर 2:30 बजे)
- 14 अप्रैल: रूस बनाम भारत (दोपहर 2:30 बजे)
- 17 अप्रैल: रूस बनाम भारत (दोपहर 2:30 बजे)
- स्थान: मात्सेस्टा फुटबाल सेंटर, सोची।

न्यूज ब्रीफ

फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले कोलंबिया को राहत: जेम्स रोड्रिगेज ट्रेनिंग पर लौटे

लास एंजेलिस/मिनेसोटा। कोलंबिया के स्टार फुटबालर जेम्स रोड्रिगेज से जुड़ी स्वास्थ्य चिंताओं के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। गंभीर डिहाइड्रेशन के चलते अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वह अब अपने क्लब मिनेसोटा यूनाइटेड के साथ ट्रेनिंग पर लौट आए हैं। 34 वर्षीय रोड्रिगेज पिछले सप्ताह तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। उन्हें 29 मार्च को फ्रांस के खिलाफ खेले गए मैच के बाद तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां जांच में गंभीर डिहाइड्रेशन की पुष्टि हुई। शुरुआत में अमेरिकी मीडिया में उनकी स्थिति को लेकर गंभीर बीमारी (रैबडोमायोलिसिस) की आशंका जताई गई थी, लेकिन मिनेसोटा यूनाइटेड ने इन खबरों का खंडन किया। क्लब ने स्पष्ट किया कि मेडिकल जांच में ऐसी किसी गंभीर बीमारी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। क्लब के अनुसार, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रोड्रिगेज घर पर आराम कर रहे थे और अब उन्होंने नियंत्रित ट्रेनिंग सत्र के साथ मैदान पर वापसी की है। उनकी पूर्ण रूप से टीम ट्रेनिंग में वापसी क्लब के मेडिकल स्टाफ की निगरानी और उनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार होगी। गौरतलब है कि जेम्स रोड्रिगेज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कोलंबिया टीम के अहम खिलाड़ी हैं। ऐसे में उनकी फिटनेस टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

आवेश बल्ला जमीन पर मारने के कारण विवादों में आये

नई दिल्ली। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज आवेश खान पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए मैच में आचारसंहिता उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इस मैच के अंतिम ओवर के दौरान जैसे ही कप्तान ऋषभ पंत ने विजयी रन बनाये। आवेश ने जीत की खुशी में बल्ला मैदान पर मार दिया। इसी को लेकर आपत्ति जतायी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आवेश इस प्रकार की हरकतें पहले भी करते रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस प्रकार से बल्ला मारे जाने को नियमों का उल्लंघन करार दिया है। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि पेनल्टी के रूप में विरोधी टीम को 5 रन दिए जाने चाहिए थे। वहीं पूर्व अंपायर अनिल चौधरी ने आवेश खान ने सच में नियमों का उल्लंघन किया है। चौधरी का कहना है, आवेश ने जल्दी जश्न मनाते हुए बल्ला मैदान पर लगा दिया। पहले भी एक मैच में आरसीबी के खिलाफ उन्होंने जीतने के बाद हेलमेट फेंक दिया था, जिसके बाद उन पर फाइन लगा था। उन्हें इस प्रकार नियमों का उल्लघन नहीं करना चाहिये। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार सनराइजर्स हैदराबाद के प्रबंधन ने आवेश के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मामले की शिकायत भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई से की जाएगी।

अश्विन ने आईपीएल से संन्यास के कारणों का खुलासा किया

चेन्नई। पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने साल 2025 में अचानक ही इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास की घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि वह विदेशी लीग में खेलने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। वहीं अब एक साल बाद अश्विन ने खुलासा किया है कि चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में रहते हुए उन्हें मानसिक परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा था जिसके कारण उन्हें सन्यास की घोषणा करनी पड़ी। अश्विन के अनुसार अगर उस तरह की परेशानी नहीं आती तो वह इतनी जल्दी आईपीएल नहीं छोड़ते और कुछ समय इस लीग में बने रहते। अश्विन ने साल 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके एक साल बाद उन्होंने आईपीएल से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। इस स्पिनर ने कहा कि उन्होंने फ्रेंचाइजी को उनके भविष्य के बारे में फैसला करने के संशय से बचाने के लिए स्वयं ही आईपीएल छोड़ दिया था। अश्विन ने कहा, मेरा सीएसके के साथ सत्र अच्छा नहीं रहा था। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से निराशाजनक सत्र था। सच कहूं तो मुझे लग रहा था कि मैं और खेल सकता हूं पर मैंने अचानक ही इसलिए संन्यास ले लिया क्योंकि में भावनात्मक रूप से कई अन्य चीजों को साथ लेकर नहीं खेल सकता था। अश्विन ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा करने से पहले 2025 के सत्र में कम अवसर किए जाने के बाद सीएसके से कहा था कि उनकी भूमिका को स्पष्ट किया जाये।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 : सोफी स्टेडियम के कर्मचारियों की चेतावनी, मांगें न मानी गईं तो हड़ताल संभव

लास एंजेलिस

फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले लास एंजेलिस स्थित सोफी स्टेडियम में काम करने वाले करीब 2,000 फूड सर्विस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन ने बड़ा कदम उठाया है। यूनियन ने मांग की है कि टूर्नामेंट के दौरान अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) को वर्ल्ड कप संचालन से दूर रखा जाए, अन्यथा कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं।

यूनाइट हियर लोकल 11, जो इस स्टेडियम में कुक, सर्वर और बारटेंडर का प्रतिनिधित्व करता है, ने सोमवार को कहा कि वर्ल्ड कप नजदीक आने के बावजूद कर्मचारियों के पास अब तक कोई श्रम अनुबंध नहीं है।

यूनियन ने फीफा और स्टेडियम के मालिक क्रोंके स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें आईसीई और बार्डर पेट्रोल की किसी भी भूमिका को लेकर सार्वजनिक आश्वासन, यूनियन कर्मचारियों की नौकरी और कार्य परिस्थितियों की सुरक्षा, तथा हास्पिटैलिटी कर्मचारियों के लिए किफायती आवास का समर्थन शामिल है।

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के कार्यवाहक निदेशक टाड लायंस ने हाल ही में कहा था कि वर्ल्ड कप में आईसीई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बयान पर यूनियन ने चिंता जताते हुए कहा कि इससे लास एंजेलिस में कामगारों और दर्शकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

इस मुद्दे पर फीफा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि सोफी स्टेडियम प्रबंधन ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

यूनियन ने यह भी मांग की है कि टूर्नामेंट के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आटोमेशन का उपयोग कर कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त न की जाएं।

इसके अलावा यूनियन ने लास एंजेलिस, विशेषकर इंग्लवुड क्षेत्र में बढ़ती आवास लागत को लेकर भी चिंता जताई है और वर्कफोर्स हाउसिंग फंड, शार्ट-टर्म रेंटल पर नियंत्रण तथा किफायती आवास और प्रवासी परिवारों की सुरक्षा के लिए कर उपायों की मांग की है।

यूनियन के सह-अध्यक्ष कर्ट पीटरसन ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि फीफा और उसके कार्पोरेट प्रायोजक इस आयोजन से अरबों डालर कमाएंगे, लेकिन आयोजन को सफल बनाने वाले कर्मचारियों की अनदेखी कर रहे हैं।

पीएसपीबी बाबा दीप सिंह बास्केटबाल टूर्नामेंट: खालसा, किरोड़ी मल, स्टनर अकादमी और रामजस ने जीत के साथ की शुरुआत

नई दिल्ली। पांचवें पीएसपीबी बाबा दीप सिंह बास्केटबाल (पुरुष एवं महिला) टूर्नामेंट का आगाज मंगलवार को रोमांचक मुकाबलों के साथ हुआ, जिसमें मेजबान श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कालेज, किरोड़ी मल कालेज, स्टनर अकादमी और रामजस कालेज ने अपने-अपने शुरुआती मैच जीतकर जीत से शुरुआत की। पुरुष वर्ग के मुकाबले में मेजबान एसजीटीबी खालसा कालेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एमिटी यूनिवर्सिटी को 77-42 से हराया। टीम की जीत में रूपेश भाटी का अहम योगदान रहा, जिन्हें प्लेयर आफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में किरोड़ी मल कालेज ने श्री राम कालेज आफ कामर्स को 80-60 से पराजित किया। किरोड़ी मल कालेज के भाव्या को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर आफ द मैच घोषित किया गया। वहीं, महिला वर्ग में स्टनर अकादमी ने आईपी कालेज पर 76-40 से एकतरफा जीत दर्ज की। इस मैच में शेरिल के शानदार खेल के लिए उन्हें प्लेयर आफ द मैच चुना गया। वहीं, एक अन्य मुकाबले में रामजस कालेज ने किरोड़ी मल कालेज को 40-28 से हराकर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की। इस मुकाबले में वेदा श्रीवास्तव को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर आफ द मैच का पुरस्कार मिला।

ग्रीन को तीसरे नंबर पर उतार कर गलती कर रही केकेआर: पीटरसन

लंदन

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) की ओर से खेल रहे आलराउंडर कैमरुन ग्रीन को तीसरे नंबर पर उतारे जाने को सही नहीं बताया। पीटरसने के अनुसार ग्रीन नंबर तीन पर खेलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ग्रीन का प्रदर्शन भी अब तक इस सत्र में अच्छा नहीं रहा है। पंजाब किंग्स के खिलाफ भी वह शुरुआत में ही आउट हो गये थे हालांकि ये मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया। पीटसन के अनुसार ग्रीन ने इस सीरीज के तीनों मैच में मिलकार कुल 26 रन ही बनाए हैं। मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने 18, 2 और 4 बनाये। इससे पहले टी20 विश्व कप 2026 में भी वह रन बनाने में असफल रहे थे। कार्यभार प्रबंधन के तहत क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने उन्हें गेंदबाजी नहीं करने को कहा है। ऐसे में वह केवल बल्लेबाज के तौर पर ही लीग में खेल रहे हैं। इसी को लेकर पीटरसन ने कहा क , मैं उन्हें अधिक रकम दिये जाने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह खेल का हिस्सा है पर जब आप आईपीएल टीम में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हैं, तो आपके पास उस स्तर का प्रदर्शन होना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि वह नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने के लिए पर्याप्त रुप से अच्छे हैं। उन्होंने कुछ पारियां जरूर खेली हैंपर इतनी नहीं कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। पीटरसन के अनुसार ग्रीन मध्य क्रम में ही बल्लेबाजी कर सकते हैं। साथ ही कहा, वह गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उनकी भूमिका और भी सीमित हो जाती है। मेरे अनुसार वह एक मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, जो थोड़ा बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं, बस। इस पूर्व कप्तान के इस बयान के बाद ग्रीन की भूमिका और उनकी जगह को लेकर बहस और तेज हो गई है। खासकर तब जब टीम में अन्य विदेशी खिलाड़ियों को अब तक अवसर नहीं मिला है। केकेआर के पास टिम स्टीफर्ट और रचिन रविन्द्र जैसे कई जैसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक अंतिम ग्यारह में नहीं पहुंचे हैं। पंजाब के खिलाफ अवसर मिला पर वह बल्लेबाजी नहीं कर पाये। ऐसे में टीम प्रबंधन के चयन के तरीके पर भी सवाल उठने लगे हैं क्योंकि ग्रीन के खराब प्रदर्शन और गेंदबाजी न करने से केकेआर का टीम संतुलन प्रभावित हो रहा है।

पडिक्कल इसी प्रकार खेलते रहे तो भविष्य में भारतीय टीम में जगह मिलना तय : कार्तिक

नई दिल्ली। रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मेंटर दिनेश कार्तिक ने बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है जिस प्रकार से वह बल्लेबाजी कर रहे है, उससे भविष्य में उनको भारतीय टीम में जगह मिलना तय है। कार्तिक के अनुसार पडिक्कल ने पिछले कुछ से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। जिसपर चयन समिति की नजरें बनी होंगी। साथ ही कहा कि जिस तरह से वह घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं उससे भी उनकी दावेदारी मजबूत हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी इस युवा बल्लेबाज ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 29 गेंदों में तेजी से 50 रन बनाए थे। कार्तिक ने कहा कि जिस प्रकार से शुरुआती मुश्किल दौर में पारी के दौरान इस बल्लेबाज ने संयम रखा उसकी भी सराहना होनी चाहिये। कार्तिक ने कहा, सबसे पहली बात जो अह है, वह है पडिक्कल का मजबूत इरादा। इस तरह की पिच पर, जब शुरुआत में रन आसानी से नहीं बनते, तो कई बल्लेबाज बड़ा शाट खेलने की कोशिश करते हैं और अपनी विकेट खो देते हैं। जब हालात कठिन थे, तब भी धैर्य बनाए रखने के लिए देवदत्त ने बहुत हिम्मत दिखाई।

पूर्व वाडा अध्यक्ष क्रेग रीडी का 84 वर्ष की आयु में निधन

नई दिल्ली

विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) के पूर्व अध्यक्ष क्रेग रीडी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने सोमवार को उनके निधन की पुष्टि की, हालांकि मौत के कारण का खुलासा नहीं किया गया है। क्रेग रीडी खेल प्रशासन में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे और उन्होंने ओलंपिक आंदोलन तथा डोपिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वह 2013 में वाडा के अध्यक्ष बने थे और अपने कार्यकाल के दौरान रूस के डोपिंग विवाद को लेकर उनके रुख ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। रीडी ने 2012 लंदन ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने की बोली में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने बैडमिंटन को 1992 बार्सिलोना ओलंपिक खेलों में शामिल कराने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए ने रीडी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें अपना मार्गदर्शक, सलाहकार और करीबी मित्र बताया। उन्होंने कहा कि रीडी ओलंपिक खेलों के गहन ज्ञान और अनुभव के धनी थे, जिसे उन्होंने हमेशा साझा किया।

रीडी का कार्यकाल 2016 रियो ओलंपिक से पहले रूस के राज्य प्रायोजित डोपिंग घोटाले के कारण काफी चुनौतीपूर्ण रहा। वाडा की ओर से रूस की पूरी टीम को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन आईओसी और उसके अध्यक्ष थामस बाक ने इसका विरोध किया। अंतत: फैसला खेल महासंघों पर छोड़ दिया गया कि वे रूसी खिलाड़ियों की भागीदारी पर निर्णय लें।

आईओसी की वर्तमान अध्यक्ष कर्स्टी कोवेंट्री ने रीडी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि खेलों की स्वच्छता और खिलाड़ियों के विकास में उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने उन्हें खेलों की ईमानदारी का सच्चा संरक्षक बताया। स्काटलैंड के रीडी को 2006 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह 1994 में आईओसी के सदस्य बने और 2021 में मानद सदस्य बनाए गए। आईओसी ने घोषणा की है कि स्विट्जरलैंड के लाज़ेन स्थित मुख्यालय में उनके सम्मान में तीन दिनों तक झंडा आधा झुका रहेगा।

अर्जेंटीना दौरे पर जाएगी भारतीय महिला हाकी टीम

यह दौरा 2026 में होने वाले एफआईएच हाकी विश्व कप (बेल्जियम और नीदरलैंड) और एशियाई खेलों की तैयारियों के लिए अहम साबित होगा

नई दिल्ली

भारतीय सीनियर महिला हाकी टीम इस महीने चार मैचों की सीरीज के लिए अर्जेंटीना दौरे पर जाएगी। यह सीरीज 13 से 17 अप्रैल के बीच ब्यूनस आयर्स स्थित सिनार्ड में खेली जाएगी। इस सीरीज में भारत अपने घरेलू मैदान पर मजबूत दक्षिण अमेरिकी टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगा, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। मैच 13, 14, 16 और 17 अप्रैल को खेले जाएंगे, जिनका समय स्थानीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे) रहेगा।

भारत और अर्जेंटीना के बीच पिछले कुछ वर्षों में कड़े मुकाबले देखने को मिले हैं, जिसमें पिछले साल जून में एफआईएच प्रो लीग 2024-25 के दौरान 2-2 से ड्रा मुकाबला भी शामिल है, जिसका फैसला शूटआउट से हुआ था। यह दौरा भारत के लिए उच्च स्तर की अंतरराष्ट्रीय टीम के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच अभ्यास का अवसर प्रदान करेगा और हाकी इंडिया की रणनीतिक योजना के अनुरूप टीम को 2026 के एफआईएच हाकी विश्व कप (बेल्जियम और नीदरलैंड) और इस साल होने वाले एशियाई खेलों से पहले लय हासिल करने में मदद करेगा।

यह सीरीज भारत के लिए काफी अहम तैयारी साबित होगी, जिसमें टीम को चार तेज-तर्रार मैच खेलने का मौका मिलेगा। साथ ही, कोचिंग स्टाफ को खिलाड़ियों के विभिन्न संयोजन और रणनीतियों को आजमाने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि टीम अपने कैलेंडर के महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रही है।

दौरे को लेकर भारतीय महिला हाकी टीम के मुख्य कोच श्योर्ड मारिन ने कहा, हम 24 खिलाड़ियों के दल के साथ अर्जेंटीना जा रहे हैं और यह एक सोचा-समझा फैसला है। इस दौरे का मकसद ज्यादा खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर प्रदर्शन का मौका देना है। अर्जेंटीना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है और वहां का माहौल हमें बताएगा कि हर खिलाड़ी किस स्तर पर खड़ा है। हम देखना चाहते हैं कि दबाव के समय कौन खिलाड़ी आगे आता है।

उन्होंने आगे कहा, इस टीम में जगह बनाने के लिए सबसे पहले एक टीम खिलाड़ी होना जरूरी है। व्यक्तिगत क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप टीम के साथ तालमेल नहीं बैठा सकते और एक-दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते, तो इस टीम में जगह बनाना मुश्किल होगा।

कितनी देर धोएं हाथ

साबुन से अच्छी तरह झाग बनाकर करीब 20 सेकेंड तक हाथ धोना सही रहता है। जरूरी नहीं कि आप एंटी बैक्टीरियल साबुन का ही इस्तेमाल करें। कोई भी साबुन कीटाणुओं को मारने में कारगर हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे उंगलियों के बीच में और नाखूनों के आसपास भी अच्छी तरह से हाथ धोएं। और हां कलाई साफ करना न भूलें।

सुखाने के लिए तौलिया हो सही

हाथ धोने के बाद उसे तौलिये से पोंछ लें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा जिस तौलिये से हाथ साफ कर रहा है वह साफ और सूखा हो। गंदे तौलिये से हाथ साफ करने से बच्चे के हाथ पर दोबारा कीटाणु जमा हो सकते हैं। और ऐसे में उसका हाथ धोना बेकार जाएगा।

हाथ धोने की महत्ता को नजरअंदाज न करें। हाथों की सफाई पर लगाए गए चंद सेकेंड आपके और आपके बच्चे को डॉक्टर के पास लगने वाले कई चक्करों से बचा सकते हैं।

बाइक्स के लिए स्मार्ट एमरजेंसी सिस्टम

कारों तथा अन्य चौपहिया वाहनों में सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एमरजेंसी सिस्टम लगाया जाता है जोकि गंभीर हादसों के दौरान जानें बचाने के काम आता है पर इस तरह का स्मार्ट एमरजैंसी सिस्टम दोपहिया वाहनों में देखने को नहीं मिलता, हालांकि दोपहिया वाहनों को भी सुरक्षा की उतनी ही जरूरत होती है जितनी चौपहिया वाहनों को। इस बात का ध्यान रखते हुए बीएमडब्ल्यू द्वारा मोटरसाइकिलों के लिए भी स्मार्ट एमरजेंसी सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जो एमरजेंसी तकनीक मोटरसाइकिलों के लिए बनाई जा रही है इसमें इंटेलीजेंट एमरजेंसी काल की सुविधा दोपहिया वाहनों में हादसों के दौरान होने वाले जान-माल के नुक्सान को बचा सकती है। इसमें दिए गए आटोमैटिक रिस्पांस सिस्टम के कारण यह भी कहा जा रहा है कि इसमें आर्टीफीशियल इंटैलीजैंस का इस्तेमाल भी किया गया है। बीएमडब्ल्यू द्वारा तैयार किया गया इंटेलीजैंट एमरजैंसी काल यानी आईईसी सिस्टम और लीन एंगल सैंसर्ज न सिर्फ बाइक के गिरने या क्रैश होने की खबर देते हैं बल्कि इसके साथ जल्दी ही सहायता के लिए एमरजेंसी कॉल भी करते हैं। यदि एक्सीडेंट अधिक गंभीर है तो एमरजेंसी काल के साथ-साथ यह सिस्टम आपकी लोकेशन भी साथ में सैंड करता है। अगर एक्सीडेंट छोटा है तो आपके पास एमरजैंसी काल को कैंसिल करने का भी समय होगा। भारत, अमरीका आदि में यह टैक्नोलॉजी इतनी जल्दी नहीं आने वाली पर आई.सी.ई. को सबसे पहले जर्मनी में 2017 के करीब लांच किया जाएगा तथा इसके बाद इसको यूरोप के अन्य देशों में फैलाया जाएगा। अन्य देशों में इसकी उपलब्धता के बारे कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि कम्पीटिशन को देखते हुए इस टैक्नोलाजी में प्रयोग किए जाने वाले टूल्स को अन्य कम्पनियां भी कॉपी कर सकती हैं।

भविष्य का वाहन होवरबाइक...

ब्रिटेन के कोलिन फ्रूज ने भविष्य के वाहन यानी उड़ने वाली बाइक का अविष्कार किया है। इसका नाम होवरबाइक रखा गया है। उसने दो पैराजेट मोटरों को एक विशाल पंखे की शक्ल दी है, जिससे बाइक ऊपर उठती है। कोलिन ने इस अविष्कार के चार वीडियो जारी किए हैं। इसमें बाइक की बनावट के साथ ही यह किस तरह उड़ती है, इसकी जानकारी दी गई है। वीडियो में कोलिन जमीन से उड़ते हुए हवा में पहुंच जाते हैं। वीडियो यू-ट्यूब पर उपलब्ध है। उन्होंने इसे बनाने के तरीके भी बताए हैं। लोगों के सुझाव पर बनाया कोलिन को इस वाहन को बनाने का सुझाव हजारों दर्शकों से मिला। उन्होंने उड़ने वाली बाइक तो बना ली है, लेकिन यह बाजार में आएगी या नहीं या कब तक आएगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

अब ई-बाइक्स की डिमांड

निजी परिवहन के लिए बहुत से व्हीकल्स यानी मोटरसाइकिल्स, कारें आदि मार्केट में उपलब्ध हैं लेकिन निजी वाहन के रूप में इलैक्ट्रिक साइकिल्स यानी ई-बाइक्स का विस्तार हो रहा है और ई-बाइक्स इस मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा बनती जा रही हैं। इस समय कई कंपनियां ई-बाइक्स बना रही हैं। अब जियोऑर्बिटल व्हील पर भी काम हो रहा है जो आपकी साधारण को ई-बाइक में बदल देगा।

ऑटो वर्ल्ड में सिर्फ इलैक्ट्रिक कारों ने ही अपनी जगह मजबूत नहीं की है, फ्यूल की बढ़ती कीमत के कारण इलैक्ट्रिक बाइक्स और ई-बाइक्स यानी इलैक्ट्रिकल साइकिल की डिमांड भी बढ़ी है। एक रिसर्च के मुताबिक 2014 में ग्लोबल ई-बाइक की बिक्री 32 मिलियन तक थी जो 2023 तक 40 मिलियन तक हो जाएगी। अब तो ई-बाइक्स में इनोवेटिव फीचर्स यानी स्मार्टफोन से कनैक्ट करने वाले फीचर्स भी दिए जा रहे हैं। आइए एक नजर ऐसी ही इनोवेटिव ई-बाइक्स पर डालते हैं।

बैटियन साइकिल्स

आम इस्तेमाल के लिए प्रयोग होने वाली टाइटैनियम और कार्बन फाइबर से बनी बाईसाइकिल्स पहले से ही बहुत स्पैशल है और यह तब और भी स्पेशल बन जाती हैं जब इन्हें आर्डर पर बनाया जाए। ऑस्ट्रेलिया के बैटियन साइकिल्स ने चीजों को और भी बदल दिया है। हाल ही में उन्होंने पहले ऐसे मॉडल की घोषणा की है जिसमें फिलामैंट-वाऊंड कार्बन ट्यूब्स जिन्हें टाइटेनियम लग्स से एक-दूसरे से जोड़ा गया है, को 3डी प्रिंटर से बनाया गया है। लेजर की मदद से एयरोस्पेस टाइटेनियम पाऊडर को पिघलाकर एक इंच के हजारवें भाग का निर्माण मोटी परतों के रूप में किया जाता है। एक साइकिल के सभी लग्स को एक बार में ही बनाया जाता है जिससे यह पार्ट्स एक दिन से भी कम समय में बन जाएंगे। कार्बन ट्यूब्स को बाद में लग्स में लगाया जाता है और अपनी जगह पर लगा दिया जाता है। इस सिस्टम का एक फायदा यह है कि अगर यह ट्यूब्स टूट जाएं तो इन्हें अलग से बदला जा सकता है।

स्टाइलिश ओको

सबसे स्टाइलिश ई-बाइक्स में से एक। फार्मूला 1 रेस कार मैटीरियल से बनाई गई है ओको। सिंगल चार्ज पर 40 किलोमीटर तक चल सकती है। यह बाइक डच कम्पनी बायोमेगा ने बनाई है और इसका वजन 40 पाऊंड है।

कुछ खास है जिंजी

जिंजी में रिमूवेबल बैटरी लगी है। पैडल, थ्रोटल और एनालॉग 3 मोड्स दिए गए हैं। लाइटवेट बैटरी पैक जो 4 घंटों में चार्ज हो जाती है। 32 किलोमीटर तक की रेंज। स्पीड, पैडल एसिस्ट लैवल्स, ई-बाइक मोड और अन्य कंट्रोल्स के बारे में बताता है इसमें लगा एलसीडी पैनल। ई101 और ई102 मॉडलों में उपलब्ध।

लीयाओस सोलर

लीयाओस सोलर में सोलर टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे बैटरी अपने आप चार्ज होती रहती है। बाइक के दोनों तरफ लगे हैं सोलर पैनल। प्लस से चार्ज करने पर लगते हैं 2 घंटे। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है।

जी फ्लाईबाइक

जी फ्लाईबाइक को एप से लॉक कर सकते हैं। यू.एस.बी. पोर्ट और पैडल की मदद से चार्ज हो जाती है। आसानी से फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं। सिंगल चार्ज पर 40 मील यानी 64 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है।

वैनमूफ इलेक्ट्रीक एस

वैनमूफ इलेक्ट्रीक एस नाम की ई-बाइक को इंटरनैट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एप की मदद से हाथों में होगा सारा कंट्रोल। एप की मदद से स्पीड भी कर सकते हैं कंट्रोल। 32 कि.मी. की टॉप स्पीड और 112 कि.मी. तक की रेंज।

जियोऑर्बिटल व्हील का कमाल

अगर आपके पास बाइक है तो क्या आप इसे महज 60 सैकेंड के अंदर ई-बाइक में बदल सकते हैं।
जियोऑर्बिटल नामक यह व्हील आपकी बाइक को ई-बाइक बनाने में मदद करेगा। पिछले एक-दो सालों से जियोऑर्बिटल पर काम हो रहा था लेकिन अब इसे पूरी तरह से बना लिया गया है और जियोऑर्बिटल को किकस्टार्टर कैम्पेन के तहत लांच किया गया है ताकि इसके लिए प्री-आर्डर और पैसे इकट्ठे किए जा सकें।

कैसे करता है काम

जियोऑर्बिटल एक व्हील है जो आपके बाइक के आगे वाले व्हील की जगह लगाया जाएगा और इससे आपकी साधारण बाइक इलैक्ट्रिक बाइक में बदल जाएगी। इस व्हील में छोटे इलैक्ट्रिक व्हील लगे हैं जो रिम को घुमाने में मदद करते हैं। किसी गियर की तरह ये छोटे व्हील्स रिम को पकड़े रखते हैं जिससे बाइक को गति मिलती है। बाइक को चलाने के लिए 500 वॉट की मोटर मदद करती है और व्हील के अंदर ही 36 वोल्ट की बैटरी भी लगी है।
जियोऑर्बिटल रिम में 3 व्हील्स लगे हैं लेकिन इसमें से एक ही इलैक्ट्रिक पावर पर चलता है बाकी के 2 स्थिरता के लिए हैं।

फ्लैट टायर

इस व्हील को सॉलिड फोम से बनाया गया है जिस पर फ्लैट टायर लगे हैं और इसका वजन 9.07 किलोग्राम है। जहां तक थ्रोटल की बात है तो यह छोटे से लीवर के रूप में आता है जिसे हैंडल बार पर अटैच किया जा सकता है जिसमें एक पावर बटन लगा है। इस बटन से व्हील घूमता है और बैटरी इंडीकेशन के लिए लाइट्स लगी हैं।

टायर कुछ अलग हटके

आपने कितनी बार ऐसी कारें देखी हैं, जो सामान्य से बड़े पहियों और टायर पर दौड़ती नजर आती हैं। ये टायर आपकी कार में फिट टायरों से जरा अलग हटके होते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत कम ही ऐसी कारें देखी हों, जिनमें इस तरह के टायर होते हैं।आप इन कारों में जो टायर देखते हैं वे वास्तव में बाजार में आने के बाद करवाया गया संशोधन होता है। इसमें बड़े व्हील रिम और लो-प्रोफाइल टायरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये टायर सामान्य टायरों की अपेक्षा पतले होते हैं ताकि बड़े व्हील पुराने व्हील खांचे में ही सेट हो जाएं। हालांकि, ये टायर जरा हटकर नजर आते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप इन्हें खरीदने के लिए दौड़ पड़ें कुछ बातों का खयाल जरूर रखना चाहिए।

टायर का साइज कैसे पढ़ें

हर टायर पर अन्य जानकारियों के साथ ही टायर का साइज भी लिखा होता है। आप टायर पर ये सभी जरूरी जानकारियां देख सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ टायर पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। टायर के साइज की जानकारी 305/30जेडआरवी9 के रूप में लिखी नजर आ सकती है। जिसका अर्थ होता है, 305 यानी मिलीमीटर में टायर की चौड़ाई 30, टायर के प्रोफाइल या पहलू अनुपात के बारे में जानकारी। टायर की स्पीड रेटिंग। यहां जेड रेटिंग का अर्थ है 300 किलोमीटर/घंटे से अधिक की रफ्तार।

टायर प्रोफाइल

टायर प्रोफाइल टायर के साइडवॉल की गहराई होती है या टायर के साइड की ऊंचाई होती है। इसे टायर की चौड़ाई के कुछ प्रतिशत के रूप में माना जाता है। हमारे उदाहरण में देखें, तो 305/30जेडआरवी9 टायर, प्रोफाइल या पहलू अनुपात बहुत कम यानी 30 है। इसका अर्थ है कि टायर के साइडवॉल की गहराई 305 मिलीमीटर का 30 फीसदी है। लो प्रोफाइल टायरों का पहलू अनुपात आमतौर पर 60 से शुरू होता है। और जैसे-जैसे साइड वॉल पतली होती जाती है यह संख्या कम होती जाती है।

इन टायरों का फायदा

ये टायर आपकी कार के लुक्स को शानदार तरीके से बढ़ाते ही हैं साथ ही हैंडलिंग और ग्रिप बेहतर हो जाती है, खासकर गर्मी के दिनों में। इसके साथ ही आपके कार की ब्रेक भी बेहतर हो जाती है। इसमें टायर का अधकि हिस्सा जमीन के साथ लगता है, इससे यह सामान्य टायर के मुकाबले अधिक कर्षण देता है। लो प्रोफाइल टायर आपकी कार के कॉर्नर को खूबियां देता है। टायर के कोने चौड़े होने के कारण यह कॉर्नर फोर्सेज का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टीयरिंग की क्षमता में भी इजाफा हम साफ तौर पर देख सकते हैं।

इन टायरों के नुकसान

भारतीय परिदृश्य के संदर्भ में लो-प्रोफाइल टायरों और रिम को पहुंचने वाला नुकसान अतिसंवेदनशील है। क्योंकि इन टायरों में हवा का दबाव कम होता है, इसलिए यह खराब कंकर-पत्थर वाली सड़कों पर इन टायरों से चलना बहुत मुश्किल हो सकता है।

बारिश में सावधानी

लो-प्रोफाइल टायरों के साथ आपको बारिश के दिनों में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। ये टायर गीले होने पर कम एक्वाप्लानिंग देते हैं। एक्वाप्लानिंग उस स्थिति को कहते हैं जब टायर और सड़क के बीच पानी की परत बन जाती है।

सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली एमपीवी

भारतीय बाजार में हैचबैक कारों की अच्छी पकड़ है लेकिन, इन दिनों ये देखा जा रहा है कि ग्राहक नए सेगमेंट की कारों में भी काफी रुचि दिखा रहे हैं। एक वक्त एमपीवी सेगमेंट की कारों को कुछ खास पसंद नहीं किया जाता था लेकिन बीते कुछ सालों में इसमें बड़ा बदलाव देखा गया है। ग्राहक एमपीवी सेगमेंट की गाड़ियों में खासा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस सेगमेंट की कारों में ज्यादा लोगों के बैठने की सुविधा तो होती ही है साथ ही साथ ये गाड़ियां बजट के मामले में भी ग्राहकों को लुभाती हैं। इसके अलावा इन गाड़ियों का माइलेज भी काफी अच्छा होता है। हम आपको एमपीवी सेगमेंट की उन गाड़ियों के बारे में बताते हैं जिसके माइलेज को जानकर आप चौंक जाएंगे।

होंडा मोबिलियो

होंडा ब्रियो की प्लेटफॉर्म पर तैयार होंडा मोबिलियो भारत की पहली एमपीवी कार है। इस कार का डायमेंशन काफी प्रभावित करता है। होंडा मोबिलियो का व्हीलबेस 2650एमएम का है जिसकी वजह से कार के अंदर अच्छी-खासी जगह है। होंडा मोबिलियो 1.5-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इस कार का डीजल वेरिएंट 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। इसका माइलेज 24.5 किलोमीटर प्रति लीटर है।

मारुति सुजुकी अर्टिगा

मारुति सुजुकी अर्टिगा पहली कॉम्पैक्ट एमपीवी है जिसमें इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दी। यह एमपीवी देखने में बहुत बड़ी नहीं है लेकिन इस कार में 7 लोगों के बैठने की सुविधा है। मारुति सुजुकी अर्टिगा पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इस कार के डीजल वेरिएंट में फिएट द्वारा तैयार 1.3-लीटर डीजल इंजन लगा है जो 88.8 बीएचपी का पावर और 200एनएम का टॉर्क देता है। इस कार का माइलेज 20.77 किलोमीटर प्रति लीटर है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली एमपीवी है। इसका माइलेज 20.77 किलोमीटर प्रति लीटर है।

डैटसन गो प्लस

निसान की लो-कॉस्ट ब्रांड डैटसन ने भी भारत में सब-4 मीटर एमपीवी को बाजार में उतारा है। डैटसन गो प्लस की लंबाई 3995एमएम, चौड़ाई 1635एमएम और ऊंचाई 1490एमएम है। वहीं इस कार का व्हीलबेस 2450एमएम है। इस कार के पिछले रो की सीट पर बमुश्किल बच्चों को बैठाया जा सकता है। कार का बूटस्पेस 48 लीटर का है जिसे तीसरे रो की सीट को फोल्ड करने के बाद 347 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। डैटसन गो प्लस में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन लगा है जो 67 बीएचपी का पावर और 104एनएम का टॉर्क देता है। इसका माइलेज 20.6 किलोमीटर प्रति लीटर है।

रेनो लॉजी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में डासिया लॉजी नाम से मशहूर इस कार को भारत में रेनो लॉजी के नाम से लॉन्च किया गया था। रेनो लॉजी को रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस कार का व्हीलबेस 2810एमएम का है और इसमें 7 से 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कार में 1.5-लीटर के9के डीजल इंजन लगा है जिसे दो तरीके से ट्यून किया गया है। ये कार 84 बीएचपी और 108 बीएचपी पावर ऑप्शन के साथ मौजूद है। इस कार में वही इंजन लगाया गया है जिसे रेनो डस्टर में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल ये कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है।इसका माइलेज 19.98 किलोमीटर प्रति लीटर है।

महिंद्रा जाइलो

इस लिस्ट में सबसे पुरानी गाड़ी महिंद्रा जाइलो है। कार की लंबाई 4250एमएम और व्हीलबेस 2760एमएम है। कार का इंजन लगा है 118 बीएचपी का पावर और 280एनएम का टॉर्क देता है। इसका माइलेज 14.02 किलोमीटर प्रति लीटर है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**